



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]
No. 52]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 27, 2007/फाल्गुन 8, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 27, 2007/FALGUNA 8, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2007

अंतिम जांच परिणाम

विषय : यू ए ई एवं ईरान के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सफेद सीमेंट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी निर्णायक समीक्षा ।

सं. 15/6/2005/डीजीएडी.-वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन एवं उन पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का संकलन एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. पृष्ठ भूमि

2. यतः उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने 6.12.2000 को यू ए ई तथा ईरान के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सफेद सीमेंट के कथित पाठन की पाटनरोधी जांच प्रारंभ की थी और प्राधिकारी के 22.2.2001 के प्रारंभिक जांच परिणामों के आधार पर सीमाशुल्क अधिसूचना सं0 64/2001 सीमाशुल्क, दिनांक 14.6.2001 के द्वारा यू ए ई तथा ईरान से सफेद सीमेंट के आयात पर अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों को दिनांक 30.8.2001 की अधिसूचना के जरिए अधिसूचित किया गया था और राजस्व विभाग ने दिनांक 3.10.2001 की अधिसूचना सं0 99/2001-सीमाशुल्क के जरिए संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था ।

3. उक्त अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उचित रूप से प्रमाणित आवेदन, जिसमें अगले पाँच वर्ष की अवधि के लिए शुल्क की समीक्षा, उसे जारी रखने तथा उसमें सुधार का अनुरोध किया गया था, के आधार पर प्राधिकारी ने ग्रह जाँच करने के लिए कि क्या शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन और/अथवा क्षति के जारी रहने या पुनः प्रारंभ होने की संभावना है, दिनांक 28 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं० 15/6/2005-डी जी ए डी के जरिए उक्त उपाय के लिए एक निर्णायक समीक्षा प्रारंभ की। 1 अक्टूबर, 04 से 30 सितम्बर 2005 (जाँच अवधि) (12 महीने) के लिए जाँच की गई थी, तथापि जाँच अवधि सहित वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 की अवधि के लिए क्षति विश्लेषण किया जाएगा।

4. जाँच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है :-

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत मै० ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि० (सफेद सीमेंट प्रभाग), खड़िया खंगार - जोधपुर, राजस्थान के समर्थन से मै० जे के व्हाइट सीमेंट वर्क्स (जे के सीमेंट लि० की इकाई), गोदान-नागौर-राजस्थान द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें संयुक्त अरब अमीरात (यू ए ई) तथा ईरान (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सफेद पोर्टलैंड सीमेंट (जिसे एतदपश्चात सफेद सीमेंट या संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात से संबंधित पाटनरोधी शुल्कों की समीक्षा, उन्हें जारी रखने तथा उनमें सुधार हेतु निर्णायक समीक्षा जाँच प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है।

(ii) आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना से इस बात का प्रथम दृष्ट्या औचित्य प्रदर्शित हुआ कि पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की जाँच की आवश्यकता है। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने यू ए ई तथा ईरान के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (खनिज उत्पादों से संबंधित अधिनियम के खण्ड v) के अध्याय 25 के अंतर्गत वर्गीकृत संबद्ध वस्तु के आयात से संबंधित पाटनरोधी निर्णायक समीक्षा जाँच शुरू करते हुए दिनांक 28 फरवरी, 2006 को एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई थी।

(iii) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और/या निर्यातकों को सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और उन्हें नियम 6(2) के अनुसार पत्र के जारी होने के चालीस दिनों के भीतर संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।

(iv) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और उन्हें नियम 6(2) के अनुसार पत्र जारी होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर संगत सूचना प्रदान करने तथा अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने की सलाह दी।

(v) केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) तथा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएण्डएस) से अनुरोध किया गया था कि वह जाँच की अवधि सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्योरे उपलब्ध कराएँ। भारत स्थित ईरान तथा यू ए ई के दूतावासों से अपने देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यातों के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने का विशेष अनुरोध किया गया था। सीमा शुल्क आई सी डी आयुक्त नई दिल्ली, कोचीन, नवी मुम्बई और चेन्नई से आयात आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया गया

था, क्योंकि घरेलू उद्योग के अनुसार इन पत्तनों पर आयात किए जा रहे हैं। तथापि, केवल आई सी डी, कोचीन से सूचना से प्राप्त हुई थी।

(vi) प्राधिकारी ने उक्त नियम 6(3) के अनुसार उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रतियां प्रदान कीं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उनके द्वारा अनुरोध किए जाने पर अगोपनीय आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई गई थी।

(vii) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों सहित संबद्ध देशों की सरकारों से संगत सूचना प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रश्नावली भेजी:

मै0 सावे व्हाइट सीमेंट सी, तेहरान, ईरान
मै0 उर्मिया व्हाइट सीमेंट, तेहरान, ईरान
मै0 शोमल व्हाइट सीमेंट कंपनी, तेहरान, ईरान
मै0 बेन्विड व्हाइट सीमेंट, तेहरान, ईरान
मै0 नैरिज व्हाइट सीमेंट, तेहरान, ईरान
मै0 रास अल खायमा कं0, यू ए ई

(viii) नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना के लिए संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी गई थी। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के औद्योगिक प्रयोक्ताओं और ज्ञात प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मकता के संबंध में जांच के संगत मानी गई सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया।

1. गार्डवेल इंडस्ट्रीज, पुणे
2. सोनालैक पेंट्स एंड कोटिंग्स लि0, कथुआ
3. गोल्डन पेंट्स एंड केमिकल्स, अमृतसर
4. सुपर केम पेंट प्रा0 लि0, जालंधर
5. मार्वल पेंट कं0, लुधियाना
6. क्रेट इंडस्ट्रीज, सोलन
7. मीना इंडस्ट्रीज, शिवकाशी
8. रेनबो कलर्स इंडिया, करनाल
9. ओरिएण्टल कलर एंड पेंट प्रा0 लि0
10. एक्वोलैक पेंट्स, नई दिल्ली
11. पेगासस इंडियन टेक्सटाइलेटीज, वसई
12. एक्रो पेंट्स लि0, भिवाड़ी (राजस्थान)
13. पूना पेंट्स एंड वार्निशिंग प्रा0 लि0
14. एवरशाइन पेंट्स एंड केमिकल इंडस्ट्री, नई दिल्ली
15. पावर प्वाइन्ट (इ.) नोएडा
16. सुपर एक्वाकेम (इंडिया) प्रा0 लि0, गुडगांव

17. रेनबो कंक्रीट्स (प्रा०) लि०, पंचकुला
18. ब्राइट पेंट एंड केमिकल कं०, साहिबाबाद
19. स्नोकेम इंडिया लि०, गोदान
20. निटको कोटिंग इंडस्ट्रीज, कानपुर
21. सुपर कोट्स पेन्ट्स (प्रा०) लि०, बंगलौर
22. यू पी आर एन एन (इलाहाबाद यूनिट), इटावा
23. सुपरमिक्स कंस्ट्रैट केम (आई) प्रा० लि०, मुम्बई
24. जय इंडस्ट्री, अहमदाबाद
25. तिस्ता डेकोकेम प्रा० लि०, सिलिगुड़ी
26. प्रवीण टाइल्स कं०, मोरवी (गुजरात)
27. त्रिवेणी कलर इंडस्ट्री, वलसाड
28. सन कोट्स, राजकोट
29. यू के पेंट्स इंडिया प्रा० लि०, ग्रेटर नोएडा
30. चौयस मौजैक टाइल्स, सिलवासा
31. यूनिस्टोन प्रॉडक्स (इंडिया) प्रा० लि०, नई दिल्ली
32. संतोष टाइल्स, सिलवासा
33. वल्ली पेंट्स, चेन्नई
34. सेराकेम कोटिंग इंडिया प्रा० लि०, पुणे
35. विघ्नेश्वर इंडस्ट्रीज, शिवकाशी
36. जेम केमिकल्स, औरंगाबाद
37. एस के टाइल्स, रायपुर
38. लैटिक्रेट इंडिया प्रा० लि०, हैदराबाद
39. कोणार्क फ्लोरिंग, हुबली
40. अनुग्रह टाइल्स एंड मार्बल्स, बंगलौर
41. रेनबो कलर केम्स, तिरुनेवेली
42. एरीज इंडस्ट्रीज, पांडिचेरी
43. जेमिनी पेंट्स, चेन्नई
44. मद्रास सीमेंट लि०, कांचीपुरम
45. कॉमट्रस्ट सुपर डिजाइनर टाइल्स (प्रा०) लि० पलक्कड
46. क्रिमसन पेंट्स प्रा० लि०, कोलकाता
47. ग्राइंडकेम यूनिट II, जमशेदपुर
48. यूनीकेम पेंट्स (ई) प्रा० लि०, गुवाहाटी
49. गेंगारा मार्केटिंग एजेंसी, केरल

निम्नलिखित पक्षकारों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन/उत्तर/सूचना प्रस्तुत की है:-

- (1) सुपर एक्वाकेम (इंडिया) प्रा० लि०

- (2) इंडिया स्मॉल स्केल पेंट एसोसिएशन
- (3) अनुग्रह टाइल्स एंड मार्बल्स, बंगलौर
- (4) श्री एच. बंदूर - बंगलौर

(ix) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रकट करने का अवसर प्रदान करने के लिए दिनांक 7 नवम्बर, 2006 को एक सार्वजनिक सुनवाई की जिसमें जे के सीमेंट लि० ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि०, टी पी एम परामर्शदाता (जे के सीमेंट तथा ग्रासिम इंडस्ट्रीज के परामर्शदाता) तथा यू ए ई सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। यू ए ई के निर्यातक के अधिवक्ता भी सुनवाई में उपस्थित हुए थे। सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित पक्षकारों को मौखिक रूप से प्रकट किए गए विचारों को लिखित रूप से प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मौखिक रूप से प्रस्तुत विचार/सूचना पर खण्डन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त इन लिखित प्रस्तुतीकरणों पर विचार किया है।

(x) प्राधिकारी द्वारा जाँच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों एवं प्रस्तुत की गई सूचना/साक्ष्य पर उस सीमा तक उचित रूप से विचार किया गया है जहाँ तक उन्हें साक्ष्य द्वारा समर्थित और वर्तमान जाँच के संगत माना गया है।

(xi) जाँच की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना, जिस पर यह जाँच परिणाम आधारित है, की तथ्यपरकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने संगत एवं आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग का मौके पर सत्यापन किया। घरेलू उद्योग से क्षति के संबंध में अतिरिक्त/अनुपूरक ब्यौरे मांग गए थे जो प्राप्त भी हुए थे।

(xii) नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन जाँच परिणामों के लिए विचार किए गए आवश्यक तथ्यों/आधारों को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट किया गया था और उस पर प्राप्त टिप्पणियों पर इन जाँच परिणामों में विचार किया गया है।

(xiii) प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश उसके द्वारा रखी गयी सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखे और उसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षण हेतु खुला रखा।

(xiv) आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के आधार पर उत्पादन की ईष्टतम लागत तथा भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत निकाली गयी थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति की समाप्ति के लिए पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क पर्याप्त होगा।

(xv) **** से इस अधिसूचना में हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पता चलता है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है।

(xvi) जांच में 1 अक्टूबर, 2004 से 30 सितम्बर, 2005 की अवधि (12 महीने और जिसे जांच अवधि कहा गया है) शामिल थी। क्षति विश्लेषण के संबंध में रुझानों की जांच में जांच अवधि सहित 2002- 2003, 2003- 2004 और 2004-05 की अवधि शामिल थी।

(xvii) जहाँ कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने अथवा अन्यथा उसे प्रस्तुत करने से मना किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहाँ प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन जांच परिणामों को दर्ज किया है।

(xviii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता संबंधी दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई है। संतुष्ट होने पर जहाँ कहीं भी वांछित था, वहाँ प्राधिकारी ने गोपनीयता प्रदान की है और ऐसी सूचना को गोपनीय मानते हुए उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है। जहाँ कहीं भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपान्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

ग. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु:

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

5. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

(i) माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से संयुक्त अरब अमीरात (जिसे एतदपश्चात् यू ए ई कहा गया है) और ईरान से सफेद सीमेंट (परिष्कृत तथा अर्द्ध-परिष्कृत स्थितियों में) के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा प्रारंभ करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की गई है।

(ii) याचिकाकर्ता ने संयुक्त अरब अमीरात (यू ए ई) तथा ईरान के उत्पादकों और/अथवा निर्यातकों द्वारा भारत में सफेद सीमेंट के पाटन के विरुद्ध लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा, उसमें वृद्धि तथा उसे जारी रखने के लिए यह याचिका दायर की है।

(iii) समीक्षा जांच होने के कारण वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच के समान है।

(iv) वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद सफेद पोर्टलैंड सीमेंट है जिसे इस याचिका तथा बाजार की भाषा में आम तौर पर सफेद सीमेंट कहा जाता है। संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पारिभाषिक शब्दावली, सूत्र, विवरण, ग्रेड्स, विश्लेषण, प्रयोग, पैकिंग, परिवहन, वर्गीकरण, प्रहस्तन तथा भंडारण संबंधी सावधानियों आदि सहित उत्पाद के सम्पूर्ण विवरण की जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में की जा चुकी है और संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रिकॉर्ड में उपलब्ध है।

(v) सफेद सीमेंट निर्माण संबंधी सामग्री है और मुख्य रूप से इसका उपयोग गैर संरचनात्मक प्रयोजनों के लिए होता है। इसका उपयोग वास्तुशिल्पीय प्रयोजनों, फ्लोरिंग, फ्लोरिंग टाइल्स के विनिर्माण, सीमेंट आधारित बाह्य पेंट्स तथा सीमेंट वॉश (सफेदी) में होता है। सफेद सीमेंट में घुलनशील एल्कलीज की मात्रा कम होती है और इससे दाग नहीं पड़ता है।

(vi) मै0 आर ए के निर्यातक भारतीय बाजार में सफेद सीमेंट के अतिरिक्त क्लिंकर की अत्यधिक मात्रा का निर्यात कर रहे हैं। क्लिंकर और कुछ नहीं बल्कि अपरिष्कृत सफेद सीमेंट है। क्लिंकर से सफेद सीमेंट प्राप्त करने के लिए अपेक्षित एकमात्र और प्रक्रिया है वृद्धिकारी तथा जिप्सम की ग्राइंडिंग एवं मिक्सिंग।

(vii) आगे सफेद सीमेंट के रूप में प्रसंस्करण के अलावा क्लिंकर का और कोई उपयोग नहीं है। क्लिंकर का आयात और कुछ नहीं बल्कि अपरिष्कृत या अप्रसंस्कृत अथवा अर्द्ध-प्रसंस्कृत सफेद सीमेंट का आयात है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता ने निवेदन किया कि क्लिंकर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।

(viii) आम तौर पर संबद्ध देशों के और विशेष रूप से ईरान के उत्पादक कम केवल सफेद सीमेंट का बल्कि अर्द्ध-परिष्कृत सफेद सीमेंट (क्लिंकर) का कई देशों को निर्यात कर रहे हैं। प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई गई है:-

(ix) ईरान से निर्यात

मात्रा मी.टन में

सफेद सीमेंट	2000-01	2001-02	2002-03
उर्मिया व्हाइट	0	15462	18822
शोमल व्हाइट	4932	1884	492
सावे व्हाइट	55809	80513	64359
नेयरिज व्हाइट	37882	29293	11844
कुल	98423	127152	95517

क्लिंकर	2000-01	2001-02	2002-03
उर्मिया व्हाइट	0	7148	9255
शोमल व्हाइट	0	0	0
सावे व्हाइट	70855	43064	102935
नेयरिज व्हाइट	53333	54020	39102
कुल	124188	104232	151292

क्लिंकर एवं सीमेंट कुल			
उर्मिया व्हाइट	0	22610	28077
शोमल व्हाइट	4932	1884	492
सावे व्हाइट	126664	123577	167294
नेयरिज व्हाइट	91015	83313	50946
कुल	222611	231384	246809

(x) ईरानी उत्पादक नियमित रूप से कई देशों को सफेद सीमेंट तथा क्लिंकर अर्थात् अर्द्ध-परिष्कृत सफेद सीमेंट का निर्यात कर रहे हैं। वस्तुतः क्लिंकर का निर्यात सफेद सीमेंट से अधिक है।

(xi) याचिकाकर्ता द्वारा यह अनुरोध करते हुए कई तर्क दिए गए थे कि इस मामले में उत्पाद के दायरे पर पुनर्विचार किए जाने और उसे पुनः स्पष्ट करने/संशोधित करने और क्लिंकर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

(xii) यद्यपि सफेद सीमेंट को पूर्व निर्धारित सीमाशुल्क उपशीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है तथापि यह संभव है कि अन्य सीमा शुल्क शीर्षों के तहत आयात किए गए हों।

(xiii) याचिकाकर्ता निवेदन करते हैं कि यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाए तो ये उत्पादक पुनः पाटन करने लगेंगे। अपनी बाजार सूचना के आधार पर याचिकाकर्ता को ज्ञात है कि संबद्ध देश के उत्पादक/निर्यातक कई अन्य देशों को पाटित कीमतों पर अत्यधिक मात्रा में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं, जो कि नीचे दी गई तालिका से भी स्पष्ट है:-

क्र. सं.	ईरान के मामले में	कीमत/ अम.डा./मी. टन	यू.ए.ई. के मामले में	कीमत/ अम.डा./मी. टन
1	उज्बेकिस्तान	75.62	बंगलादेश (साक्ष्य 1)	80.00
2	यू.ए.ई.	77.22	बंगलादेश (साक्ष्य 2)	66.00
3	तुर्कमेनिस्तान	76.56	हॉंगकॉंग	99.40
4	ताजिकिस्तान	74.62	जर्मनी	89.38
5	श्रीलंका	80.00	इरीट्रिया	103.99
6	दक्षिण अफ्रीका	80.00	तंजानिया	101.75
7	के.एस.ए.	70.39	ओमान	85.70
8	रूस	75.82	इराक	70.16
9	कतर	62.93	नीदरलैंड	90.31
10	फिलिपींस	70.00	पाकिस्तान	97.07
11	किर्गिस्तान	75.52		
12	कुवैत	75.06		
13	कजाकिस्तान	75.28		
14	इराक	74.95		
15	जार्जिया	75.75		
16	डेनमार्क	76.41		
17	अजरबैजान	76.53		
18	आर्मीनिया	76.13		
19	अफगानिस्तान	75.18		

(xiv) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर समान वस्तु है।

ग.2 आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद, समान वस्तु, वर्तमान जाँच का दायरा तथा घरेलू उद्योग के दायरे के संबंध में किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

7. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों के मूल का अथवा वहाँ से निर्यातित सफेद पोर्टलैंड सीमेंट है जिसे आम तौर पर सफेद सीमेंट कहा जाता है (वर्तमान जाँच में इसे सफेद सीमेंट कहा गया है)। विचाराधीन उत्पाद वही है जिस पर मूल जाँच में विचार किया गया था। सफेद सीमेंट एक निर्माण संबंधी सामग्री है जिसका उपयोग टाइल्स की फ्लोरिंग, सीमेंट आधारित बाहरी कार्यों, पेंट्स और सीमेंट वार्निश आदि जैसे गैर-संरचनात्मक प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

8. सफेद सीमेंट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 25 के तहत उप शीर्ष सं० 2523.21 के अंतर्गत आता है। इस उत्पाद से संबंधित अध्याय 25 का वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

अध्याय/उपशीर्ष	विवरण
अध्याय 25	लवण, सल्फर, मृदा एवं पत्थर, प्लास्टरिंग सामग्री, चूना एवं सीमेंट
25.23	पोर्टलैंड सीमेंट, एल्युमिनेस सीमेंट, स्लेग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट तथा इसी प्रकार के हाइड्रॉलिक सीमेंट, चाहे रंगे हुए या क्लिंकर के रूप में हों अथवा नहीं
2523.10 *	सीमेंट क्लिंकर
2523.1000	सीमेंट क्लिंकर
2523.21	सफेद सीमेंट कृत्रिम रूप से रंगा हुआ अथवा अन्यथा
2523.2100	सफेद सीमेंट कृत्रिम रूप से रंगा हुआ अथवा अन्यथा

9. सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है।

10. जाँच के दायरे में सीमेंट क्लिंकर को शामिल करने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है। अतः विचाराधीन उत्पाद को मूल जाँच के समान होना चाहिए।

11. जाँच शुरुआत अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया गया है:-

विचाराधीन उत्पाद सफेद पोर्टलैंड सीमेंट है जिसे सामान्यतः सफेद सीमेंट के रूप में जाना जाता है। सफेद सीमेंट निर्माण संबंधी सामग्री है और मुख्य रूप से इसका उपयोग गैर संरचनात्मक प्रयोजनों के लिए होता है। इसका उपयोग वास्तुशिल्पीय प्रयोजनों, फ्लोरिंग, फ्लोरिंग टाइल्स के विनिर्माण, सीमेंट आधारित बाह्य पेंट्स तथा सीमेंट वॉश (सफेदी) में होता है। सफेद सीमेंट में घुलनशील एल्कलीज की मात्रा कम होती है और इससे दाग नहीं पड़ता है। सफेद सीमेंट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम (अधिनियम का अनुच्छेद V जो खनिज उत्पादों से संबंधित है) के अध्याय 25 में उप शीर्ष सं० 2523.21 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, सीमाशुल्क एवं आई टी सी एच एस वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है।

12. प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों में घरेलू उद्योग ने दोहराया है कि संबद्ध देशों से सीमेंट क्लिंकर के निर्यातों की मात्रा बहुत अधिक है। सीमेंट क्लिंकर को शामिल करने के अपने अनुरोध को दोहराते हुए घरेलू उद्योग ने दोहराया है कि जिस कीमत पर सीमेंट क्लिंकर का निर्यात किया गया है, उसे भी संबद्ध देशों से सफेद सीमेंट के घाटन के पुनः प्रारंभ होने की संभावना के निर्धारण के लिए आधार के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों और जाँच

शुरूआत अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के दायरे को पूर्ववत बनाए रखने को उचित मानते हैं। अतः प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद को सफेद पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में परिभाषित करते हैं।

13. यह निर्धारित करने के क्रम में कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देशों में उत्पादित और/अथवा वहाँ से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु माना जा सकता है, निर्दिष्ट प्राधिकारी नोट करते हैं कि पहले की जाँच में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस मुद्दे की जाँच की गई है और प्राधिकारी के पूर्व निर्धारण का विरोध करने वाला कोई निवेदन निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ है। प्राधिकारी पुष्टि करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामग्री नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित अथवा वहाँ उत्पादित वस्तु के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

14. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग से संबंधित निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

- (i) वर्तमान याचिका जे.के. व्हाइट सीमेंट वर्क्स (जो जे0के0 सीमेंट लि0 की एक इकाई है) द्वारा दायर की गई है तथा ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड - व्हाइट सीमेंट प्रभाग द्वारा समर्थित है। भारत में तीन कम्पनियाँ हैं जिन्होंने सफेद सीमेंट के उत्पादन के लिए क्षमता सृजित की है।
- (ii) याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है तथा इसीलिए याचिकाकर्ता को नियमों के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' के रूप में माना जाना चाहिए। जांच की शुरूआत के बाद किसी मामले में ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने सम्पूर्ण प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत की। इन दो कम्पनियों के उत्पादन का हिस्सा भारतीय उत्पादन 95% से अधिक है। इसीलिए दो कम्पनियों को अब घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए।

घ.2 निर्यातक, आयातक, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

15. अन्य हितबद्ध पक्षकारों में से किसी ने भी इस संबंध में कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का तात्पर्य ऐसे घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण में और उससे जुड़े कार्यकलापों में पूर्ण रूप से कार्यरत हैं - या जिनका उक्त वस्तु का संचयी उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख भाग है बशर्ते कि ऐसे उत्पादक आयोजित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित न हों या वे स्वयं उसका आयात न कर रहे हैं। ऐसे मामले में इस प्रकार के उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

17. जांच अवधि में भारतीय उद्योग का उत्पादन निम्नानुसार है :-

उत्पादक	उत्पादन मी. टन में
ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि.	339171
जे.के. लाइट सीमेंट वर्क्स	223714
वी त्रावणकोर सीमेंट्स लि०.	21219
कुल भारतीय उत्पादन	584104

18. याचिकाकर्ता कम्पनी के उत्पादन का हिस्सा भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनना है। इसके अलावा याचिका का समर्थन मै० ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि० तथा त्रावणकोर सीमेंट्स लिमिटेड द्वारा किया गया था। इसीलिए ऐसा माना गया है कि पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर याचिका घरेलू उद्योग द्वारा की गई है।

19. जांच की शुरुआत किए जाने पर प्राधिकारी ने अन्य भारतीय उत्पादकों मै० ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा त्रावणकोर सीमेंट्स लिमिटेड को प्रासंगिक सूचनाएं उपलब्ध करने का निर्देश दिया था। मै० ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा त्रावणकोर सीमेंट्स लिमिटेड ने क्षति के निर्धारण के संबंध में सूचना मुहैया कराई थी तथा स्वयं को सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया था। कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना को आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया है।

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी के अभिलेखों पर उपलब्ध सूचना के आधार पर याचिकाकर्ता तथा अनुमोदनकर्ताओं का हिस्सा भारतीय उत्पादन का 100% भाग बनाता है तथा यह न्यूनतम सीमा के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

ड. अन्य मुद्दे

ड.1 घरेलू उद्योग के विचार

21. घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार मत प्रस्तुत किया है :-

- याचिका सभी पहलुओं से सम्पूर्ण थी तथा जांच से पूर्व प्राधिकारी को पर्याप्त तथा यथार्थ साक्ष्य मुहैया कराए गए थे जो निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने के लिए आधारभूत थे।
- मै० रास अल खैमाह ने पूर्ववर्ती जांच में भाग लिया था तथा एक कीमत वचनपत्र दिया था जिसका कम्पनी द्वारा कई आधारों पर उल्लंघन किया गया। इसलिए प्राधिकारी को अब वचनबद्ध को निरस्त करना चाहिए तथा इसके बजाए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना चाहिए।
- विदेशी उत्पादकों से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलने से घरेलू उद्योग के दावे की पुष्टि होती है। इन पक्षकारों ने केवल इसलिए प्रत्युत्तर नहीं दिया है क्योंकि आंकड़ों से अन्यथा यह प्रदर्शित होता है कि पाटनरोधी शुल्क को निरस्त किए जाने की स्थिति में उत्पाद काफी मात्रा में पाटित किए जाने की संभावना होती।
- यूआई के निर्यातक के प्रतिनिधि ने बिना सूचना मुहैया कराए सुनवाई में भाग लिया। न ही इसके पश्चात कोई प्रस्तुतीकरण पेश किया। निर्यातक द्वारा समय पर प्रस्तुतीकरण न दिए जाने को ध्यान में रखते हुए निर्यातक को वर्तमान जांच में कोई दलील दिए जाने या प्रस्तुतीकरण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- (v) घरेलू उद्योग का यह मत है कि निर्यातक देश द्वारा सूचित निर्यात मात्रा, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा सूचित अभियान मात्रा से अत्यधिक उच्चतर है।
- (vi) घरेलू उद्योग ने यूआई से सफेद सीमेंट के आयात को दर्शाते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी को साक्ष्य मुहैया कराए थे, जिनमें डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों में सूचित नहीं किया गया है।
- (vii) यूआई के उत्पादक ने समूची अवधि के दौरान पाटित कीमतों पर भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करना जारी रखा जिस पर इस तथ्य के मद्देनजर कि इन्हें डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों में सूचित नहीं किया गया है, ध्यान नहीं दिया गया था।
- (viii) मै0 त्रावणकोर सीमेंट्स लि0 ने याचिका का समर्थन किया है तथा यह दावा किया है कि सफेद सीमेंट पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखा जाना चाहिए। वे भारत में सफेद सीमेंट के सबसे पुराने उत्पादक हैं। कम्पनी केरल सरकार का उपक्रम है तथा यह संबद्ध देशों से पाटन किए जाने के पहले वर्ष 2000 तक कई वर्षों से लाभदायक कम्पनी रही है। कम्पनी पुनर्नी वेट प्रक्रिया का उपयोग कर रही है। यदि सफेद सीमेंट के आयात की अनुमति दी जाती है तब कम्पनी अपने माल को बेचने में असमर्थ रहेगी तथा कम्पनी मौजूदा मात्रा को प्राप्त करने में भी असमर्थ रहेगी।

ड.2 निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

22. निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- (i) सुपर एक्वासेम इंडिया प्रा.लि. ने अपनी प्रश्नावली का उत्तर दिया है कम्पनी द्वारा कोई और प्रस्तुतीकरण/दलील नहीं दी गई है।
- (ii) इण्डियन स्माल स्केल पेंट एसोसिएशन ने यह मत व्यक्त किया था कि एसोसिएशन भारत में पेंट विनिर्माताओं के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसकी सदस्यता 1600 से अधिक है। सफेद सीमेंट, इसके सदस्यों द्वारा बनाई जा रही कुछ कोटिंगों का एक अभिन्न हिस्सा है। सफेद सीमेंट पर पाटनरोधी शुल्क का जारी रहना लघु विनिर्माताओं के हितों के लिए नुकसानदायक होगा। पाटनरोधी शुल्क को जारी रखकर सरकार केवल बड़े विनिर्माताओं के हितों की रक्षा करेगी जबकि लघु पेंट इकाइयों के हितों को इससे नुकसान होगा। पाटनरोधी शुल्क लगाने से केवल स्थानीय विनिर्माताओं को संरक्षण मिलेगा। सीमेंट के ऐसे असंतुष्ट स्थानीय विनिर्माता जो यह महसूस करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना अपेक्षित है, उनके लिए एसोसिएशन, प्राधिकारी से इस मामले को उनकी विनिर्माण लागत की तुलना में उनकी अधिकतम खुदरा कीमत की जांच करने के लिए बीआईसीपी को भेजने का अनुरोध करेगा।
- (iii) अनुग्रह टाइल्स तथा मारबल्स, बंगलौर ने प्रश्नावली की एकप्रति भेजने का अनुरोध किया था जिसे भेज दिया गया है। तथापि कम्पनी ने कोई सूचना/प्रस्तुतीकरण पेश नहीं किया है।
- (iv) आरएके के अधिवक्ता ने एक पत्र प्रस्तुत किया था कि यूआई की आयात मात्रा का हिस्सा घरेलू उद्योग को बिक्री तुलना में 1% से कम बनता है तथा घरेलू उद्योग 100 अम.डा./मी. टन से कम कीमत पर सफेद सीमेंट का निर्यात कर रहा है।
- (v) श्री एच बांदुर, बंगलौर ने एक पत्र प्रस्तुत किया था और आयातों के पहुँच मूल्य से संबंधित दावे किए थे। कम्पनीने यह भी दावा किया था कि घरेलू उद्योग प्राधिकारी को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि इसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- (vi) 23 निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण को नोट किया है। जहां तक इंडियन स्मल स्केल पेंट एसोसिएशन द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसोसिएशन के किसी भी सदस्य ने प्राधिकारी को प्रासंगिक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है न ही एसोसिएशन ने यह स्थापित किया कि किस तरह पाटनरोधी शुल्क को लगाने या जारी रखने से उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच, भारतीय उत्पादकों की सत्यापित लागत संरचना पर आधारित है। इसीलिए, लागत संरचना को बीआईसीपी के जरिए सत्यापित कराया जाना अनावश्यक होगा। यह तर्क कि यूएई की आयात मात्रा का हिस्सा घरेलू उद्योग को बिक्री तुलना में 1% से कम बनता है तथा घरेलू उद्योग 100 अम.डा./मी. टन से कम कीमत पर सफेद सीमेंट का निर्यात कर रहा है। प्रासंगिक नहीं है क्योंकि जांच यह परीक्षा करने के लिए है क्या शुल्क की समाप्ति के परिणामस्वरूप पाटन और/अथवा क्षति जारी रहेगी अथवा इसकी पुनरावृत्ति होगी। आरए के द्वारा पूर्व में दिए गए कीमत वचनबद्ध से संबंधित उल्लंघन, यदि कोई हो के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उत्पादकों ने पहले ही एक पृथक याचिका दायर की है जिसका निर्णय नियमानुसार किया जाएगा।
- (vii) न ही घरेलू उद्योग ने क्षति के जारी रहने की दलील दी है, न ही प्राधिकारी ने यह पाया कि घरेलू उद्योग को लगातार क्षति का सामना करना पड़ा है। जैसाकि इन जांच परिणामों में नोट किया गया है अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को हटाने के परिणामस्वरूप घरेलू तथा आयातित उत्पाद के बी उल्लेखनीय कीमत अनंतर आएगा तथा इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की आवृत्ति की संभावना होगी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध देश के किसी निर्यातक ने प्राधिकारी को सहयोग नहीं किया है। जहाँ अभिलेखा में उपलब्ध साक्ष्य यह इंगित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने के परिणामस्वरूप पाटन तथा क्षति की आवृत्ति की संभावना बनेगा वहीं विदेशी उत्पाद या आयातक या भारत में खपतकर्ता यह स्थापित करने में असमर्थ रहे कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने के परिणामस्वरूप भारतीय उत्पादों को कोई क्षति नहीं उठानी पड़ेगी।

पाटन तथा पाटन मार्जिन की गणना**च. पाटन मार्जिन****च.1 घरेलू उद्योग के विचार**

24. घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार मत व्यक्त किया है :-

- (i) उत्पाद का पाटित कीमतों पर निर्यात किया जाना जारी है। भले ही मात्रा में गिरावट आई है तथापि जिने भी निर्यात हुए हैं; वे उल्लेखनीय पाटित कीमतों पर हुए हैं।
- (ii) निर्यातक देश यूएई के सीमाशुल्क आंकड़ों के आधार पर संग्रह किए गए साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि आयातों की भारतीय आधिकारीक सांख्यिकी में प्रतिबिम्बित वास्तविक मात्रा से उच्चतर है, जैसा कि निम्नानुसार तालिका में प्रदर्शित है।

विवरण	डीजीसीआई एंड एस के अनुसार	वास्तविक साक्ष्य के अनुसार	निर्यातक देश के आंकड़ों के अनुसार	
अवधि.....>	जांच अवधि	जांच अवधि के भीतर	2004	2005
मात्रा	0	280	2606	4014
कीमत अम.डा. मी. टन	0	100	67	90
कारखाना द्वार निर्यात कीमत	0	73.50	56.02	63.29
सामान्य मूल्य	0	108.86	108.86	108.86
पाटन मार्जिन	0	35.36	52.84	45.57
पाटन मार्जिन %	0	48.11	94.31	71.99

- (iii) सामान्य मूल्य तथा उपर्युक्त निर्यात कीमत संबंधी अनुमानों पर ध्यान देते हुए, यह देखा जाएगा कि पाटन मार्जिन अत्यधिक है। वर्तमान निर्यातों को पाटित कीमतों पर हुआ मानते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि पाटनरोधी शुल्कों को हटाने से पाटन अधिक से अधिक और ज्यादा गहन हो जाता है।
- (iv) यूएई से निर्यात कीमत पर ध्यान देते हुए यह नोट किया जाना चाहिए कि यह वह कीमत है जिस पर निर्यातक ने कीम वचनबद्धता करार के अन्तर्गत माल का निर्यात किया है। इसलिए, यह कीमत उस पूर्ण सीमा को नहीं दर्शाती जहां तक ये उत्पादक, उत्पाद का पाटन कर सकते हैं। यदि उस कीमत की जांच की जाए जिस पर तीसरे देशों को निर्यात किया जा रहा है तब यह पता चलता है कि पाटन का दायरा काफी महत्वपूर्ण है। बंगलादेश, इण्डोनेशिया, हांगकांग, जर्मनी, केन्या, चीन, बेल्जियम, दरीट्रिया, अमरीका, तंजानिया श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, ओमान, इराक, नीदरलैंड, पाकिस्तान को यूएई के एकमात्र उत्पादक द्वारा निम्नानुसार किए गए निर्यात उस सीमा को प्रतिबिम्बित करते हैं जहाँ तक निर्यातक पाटन का सहारा लेगा। यूएई तथा ईरान से संबद्ध उत्पाद का विश्व के देशों को सामान्य मूल्य से संबंधित कीमत से काफी कम कीमत पर उल्लेखनीय निर्यात हुआ है।

क्र.सं.	देश	मात्रा मी. टन	कीमत अम.डा./मी. टन	कारखाना द्वार कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %
1	उज्बेकिस्तान	34	75.62	49.99	58.87	67.12
2	यूएई	10,898	77.22	51.58	57.28	63.13
3	तुर्कमेनिस्तान	282	76.56	50.93	57.93	64.75
4	ताजिकिस्तान	628	74.62	49.00	59.87	69.71
5	श्रीलंका	28	80.00	54.35	54.51	56.64
6	दक्षिण अफ्रीका	26	80.00	54.35	54.51	56.64
7	केएसए	43,686	70.39	44.79	64.07	81.62
8	रूस	1	75.82	50.19	58.67	66.61
9	कतर	24,635	62.93	37.37	71.50	107.30
10	फिलिपींस	20	70.00	44.40	64.46	82.81
11	किर्गिस्तान	2	75.52	49.89	58.97	67.37
12	कुवैत	10,868	75.06	49.43	59.43	68.56
13	कजाकिस्तान	975	75.28	49.65	59.21	67.99
14	इराक	90,423	74.95	49.33	59.54	68.84
15	जार्जिया	4	75.75	50.12	58.74	66.78

16	डेनमार्क	1	76.41	50.78	58.08	65.12
17	अजरबैजान	1,008	76.53	50.90	57.96	64.82
18	आर्मीनिया	1,041	76.13	50.50	58.36	65.82
19	अफगानिस्तान	3,973	75.18	49.55	59.31	68.25

क्र.सं.	देश	मूल्य किग्रा.	कीमत अम.डॉ./मी. टन	कारखाना द्वारा कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %
	यूएई					
1	हांगकांग	3,923	99.40	88.80	20.06	22.59
2	जर्मनी	635	89.38	78.83	30.03	38.09
3	इथोपिया	26	20.95	10.74	98.12	913.41
4	इरीट्रिया	862	103.99	93.37	15.49	16.59
5	यूएसए	4,140	106.44	95.81	13.06	13.63
6	तंजानिया	142	101.75	91.14	17.72	19.44
7	श्रीलंका	336	114.76	104.08	4.78	4.59
8	दक्षिण अफ्रीका	1,539	113.91	103.24	5.62	5.44
9	ओमान	352	85.70	75.17	33.69	44.82
10	इराक	1,921	70.16	59.70	49.16	82.33
11	नीदरलैंड	285	90.31	79.76	29.10	36.49
12	पाकिस्तान	2,598	97.07	86.48	22.38	25.87

- (v) पाटनरोधी शुल्क के आसेपण ने एक निवारक के रूप में कार्य किया है। पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने से पाटन अधिक से अधिक और ज्यादा गहन हो जाएगा।
- (vi) भारतीय बाजार में प्रचलित कीमत तथा कीमत जिस पर विभिन्न देशों को निर्यात किए गए हैं एवं विदेशी उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताओं पर ध्यान देते हुए यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि यूएई के निर्यातक पाटन कीमतों पर भारत में अपने निर्यातों को स्थानांतरित करेंगे, यदि वर्तमान शुल्कों को हटाया जाता है। वर्तमान निर्यात कीमतों की भारत में प्रचलित कीमतों से तुलना करने पर यह पता चलता है कि भारतीय बाजार में कीमतें विदेशी उत्पादकों के लिए अत्यधिक लाभदायक हैं।
- (vii) निर्यातक देशों में सफेद सीमेंट की मांग (1) सृजित क्षमता तथा (2) वर्तमान उत्पादन स्तरों, की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कमतर है।
- (viii) यदि यह मान भी लिया जाता है कि समीक्षा जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं का कोई पाटन नहीं हुआ है तब इससे केवल यह स्थापित होता है कि वर्तमान उपायों से पाटन को रोका जा सकता है तथा यह अधिक से अधिक यह स्थापित करता है कि वर्तमान उपायों को जारी रखने की आवश्यकता है।
- (ix) निम्नांकित आंकड़े यह दर्शाते हैं कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में यूएई से पाटन के बढ़ने की संभावना है।

विवरण	इकाई	मात्रा	स्रोत
क्षमता	मी.टन	450000	ग्लोबल व्हाइट सीमेंट
उत्पादन	मी.टन	380000	2005 - 08.05.05 खलीज टाइम्स
मांग	मी.टन	120000	ग्लोबल व्हाइट सीमेंट
अतिरिक्त उत्पादन	मी.टन	260000	गणना

क्षमता उपयोग	%	84.44	गणना	
अप्रयुक्त क्षमता	%	15.56	गणना	
अप्रयुक्त क्षमता	मी. टन	70000	गणना	
अतिरिक्त क्षमता	मी. टन	330000	गणना	
भविष्य में विस्तार	मी. टन	150000	उद्योग जगत के बाज़ार स्रोत	
संभावित अतिरिक्त क्षमता	मी. टन	220000	गणना	
वर्तमान निर्यात	मी. टन	140000	गणना	
संभावित अतिरिक्त क्षमता	मी. टन	480000	गणना	
मांग के % के रूप में वर्तमान अतिरिक्त क्षमता	%	175%	गणना	
मांग के % के रूप में भावी अतिरिक्त क्षमता	%	400%	गणना	

- (x) ईरान के संबंध में, घरेलू उद्योग ने निम्नांकित सूचना मुहैया कराई है तथा ईरान में अतिरिक्त क्षमताओं की मौजूदगी का दावा किया है।

2005-06	क्षमता	उत्पादन	क्षमता उपयोग
उर्मिया व्हाइट	163,807	166346	101.55
बेनविड व्हाइट	163,809	130703	79.79
शोमल व्हाइट	89,238	41665	46.69
सावेह व्हाइट	327,618	279753	85.39
नियरिज व्हाइट	185,364	140784	75.95
कुल	929,835	759,251	81.65%
अप्रयुक्त क्षमता	170,584		
2004-05			
उर्मिया व्हाइट	163,794	181271	110.67
बेनविड व्हाइट	163,779	120427	73.53
शोमल व्हाइट	89,235	79544	89.14
सावेह व्हाइट	327,579	245422	74.92
नियरिज व्हाइट	163,809	127312	77.72
कुल	908,196	753,976	83.02%
अप्रयुक्त क्षमता	154,220		

- (xi) उत्पादक तथा निर्यातक, अन्य देशों को माल का निर्यात कर रहे हैं जैसाकि निम्नानुसार तालिका से स्पष्ट हो जाता है :-

व्हाइट सीमेंट	2000-01	2001-02	2002-03
उर्मिया व्हाइट	0	15462	18822
शोमल व्हाइट	4932	1884	492
सावेह व्हाइट	55809	80513	64359
नियरिज व्हाइट	37682	29293	11844
कुल	98423	127152	95517

विलकर			
उर्मिया क्वाइट	0	7148	9255
शोमल क्वाइट	0	0	0
सावेह क्वाइट	70855	43064	102935
नियरिज क्वाइट	53333	54020	39102
कुल	124188	104232	151292
विलकर तथा सीमेंट - योग			
उर्मिया क्वाइट	0	22610	28077
शोमल क्वाइट	4932	1884	492
सावेह क्वाइट	126664	123577	167294
नियरिज क्वाइट	91015	83313	50946
कुल	222611	231384	246809

(xii) घरेलू उद्योग ने अमरीका के सनसेट नीति बुलेटिन को भी संदर्भित किया था जिसमें यह उल्लेख है कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के पश्चात किसी देश से आयात से स्वतः पाटन की आवृत्ति की संभावना तथा पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति व्यक्त नहीं होती तथा निर्यातकों से यह स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है कि पाटनरोधी शुल्कों को हटाए जाने की स्थिति में उत्पाद के पाटन की संभावना नहीं है। वर्तमान मामले में ईरानी उत्पादकों द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है।

(xiii) यूएई से भारत को निर्यात कीमत के संबंध में घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि यह इस तथ्य के मद्देजर कि निर्यात कीमत, निर्यातिक द्वारा दी गई वचनबद्धता के कारण वास्तविक कीमत नहीं है, पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए विश्वसनीय नहीं है।

इसे इस तथ्य के द्वारा आगे और संपुष्ट किया जाता है कि निर्यातक ने वचनबद्ध कीमत से अत्यधिक कम कीमत पर पड़ोसी देश तथा अन्य देशों को सफेद सीमेंट का निर्यात किया है।

(xv) प्रकटन विवरण में दी गई टिप्पणियों में घरेलू उद्योग ने यह दोहराया है कि संबद्ध देशों से सीमेंट विलकर का निर्यात मात्रा के रूप में उल्लेखनीय है तथा वह कीमत जिस पर सीमेंट विलकर का निर्यात किया गया है, उसे संबद्ध देशों से सफेद सीमेंट के पाटन की आवृत्ति की संभावना के निर्धारण के लिए एक आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए।

च.2 निर्यातकों के विचार

25. संबद्ध देशों से किसी भी निर्यातक ने वर्तमान जांच के संबंध कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. पाटन तथा इसकी संभावना के निर्धारण के लिए विधि के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्कों को प्राधिकारी के नोट किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि यह एक निर्णायक समीखा जांच है, इसलिए शुल्क को वापस लेने की स्थिति में पाटन के जारी रहने अथवा आवृत्ति की संभावना की जांच करना अपेक्षित है।

घ.4. पाटन का जारी रहना अथवा इसकी पुनारूति

27. प्राधिकारी ने धारा 9 क (1) (ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली की प्रतियाँ भेजी थी। पाटन तथा पाटन मार्जिन के संबंध में यूएई तथा ईरान के किसी उत्पादक/निर्यातक तथा भारत के किसी आयातक से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास असहयोगी निर्यातक हेतु पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के तहत रिकॉर्ड पर उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर कार्यवाही को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उक्त नियम में यह प्रावधान है कि :-

यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को उचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सामान्य मूल्य

28. धारा 9 (क) (1) (ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है -

(i) सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियम के अनुसार यथानिर्दिष्ट तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो; या

(ii) जहाँ निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियों की वजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य या तो -

(क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किए जाने पर समान वस्तु का उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य; या

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ वस्तु मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

29. निर्दिष्ट प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक तथा निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है। आरएके के उत्पादक ने उत्तर एवं सूचना प्रस्तुत करने के लिए भी समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। तथापि, निर्यातक/उत्पादक द्वारा कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी परिस्थितियों में निर्दिष्ट प्राधिकारी धारा 9 क (1) (ग) (i) के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें व्यापार के सामान्य क्रम में घरेलू बाजार के उत्पाद की कीमत के संबंध में पर्याप्त सूचना अपेक्षित होती है। इसको ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने नियमावली में दी गई अन्य पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की संभावना की जांच की है।

30. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि निर्यातक/उत्पादक के असहयोग के कारण व्यापार के सामान्य क्रम में तीसरे देश के चयन हेतु निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए, तीसरे देश को किए गए निर्यातों के

संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है। अन्य स्रोतों से तीसरे देशों को निर्यातों के संबंध में प्राप्त सूचना की जांच से यह प्रदर्शित होता है कि ये निर्यात उत्पादन की आकलित लागत से कम हैं और इसलिए ये निर्यात पाटित कीमतों पर किए गए हैं। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी तीसरे देशों के निर्यातों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। अतः प्राधिकारी के पास एसजीए तथा लाभ सहित उत्पादन लागत के अनुसार संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य के निर्धारण के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है।

यूएई

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में यूएई के किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया है। यूएई में उत्पादक के एक प्रतिनिधि में आर ए के मौखिक कार्रवाई में उपस्थित थे। प्राधिकारी ने प्रतिनिधि के वर्तमान जांच से संगत सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी है। तथापि, निर्यातक द्वारा कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।

32. प्राधिकारी ने यूएई में भारतीय दूतावास को पत्र लिखा है और यूएई में सफेद सीमेन्ट की कीमत के बारे में सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। भारतीय दूतावास ने सूचना दी है कि उत्पाद की थोक कीमत 50 कि.ग्रा. के प्रति बैग के लिए 21- 25 दिरहम के बीच में है। यदि जांच अवधि की विनिमय दरों पर विचार किया जाए तो यह 114- 136 अम. डा./मी. टन बनती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दूतावास ने जांच के समय वर्ष 2006 में बाजार में प्रचलित कीमत के बारे में हाल ही में सूचना दी है। व्यापार की विभिन्न शर्तों एवं नियमों के संबंध में और कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के घरेलू बाजार में कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने से पहले व्यापार के सामान्य क्रम जांच हेतु आवेदन करना अपेक्षित होता है। चूंकि किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने सहयोग नहीं किया है इसलिए व्यापार के सामान्य क्रम संबंधी जांच के लिए आवेदन करना संभव नहीं है। अतः प्राधिकारी ने भारतीय दूतावास द्वारा उपलब्ध आंकड़ों/सूचना के आधार पर आगे कार्यवाही नहीं की है।

33. इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी ने निर्यातक देश में सामान्य मूल्य के संबंध में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना/तथ्यों के आधार पर आगे कार्यवाही की है। सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुमानित उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है।

ईरान

34. प्राधिकारी के ईरान में घरेलू कीमत के बारे में ईरान स्थित भारतीय दूतावास द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कीमत वर्ष 2006 के दौरान प्राप्त एक कोटेशन पर आधारित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल कीमत कोटेशन ही सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु पर्याप्त नहीं है क्योंकि सामान्य मूल्य का तात्पर्य "व्यापार के सामान्य क्रम" में निर्यातक देश के घरेलू बाजार में सप्ताह वस्तु की कीमत से होता है। किसी उत्पादक से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी व्यापार के सामान्य क्रम संबंधी जांच हेतु आवेदन करने की स्थिति में नहीं है। अतः भारतीय दूतावास से इस संबंध में प्राप्त सूचना का उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी निर्यातक देश से सामान्य मूल्य के संबंध में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना तथ्यों के आधार पर आगे कार्यवाही की है। सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुमानित उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है।

35. निर्यात कीमत

35. धारा 9 क (क) (ख) के तहत निर्यात कीमत का अर्थ है :

" किसी वस्तु के संबंध में निर्यात कीमत का तात्पर्य निर्यातक देश अथवा क्षेत्र से निर्यातित कीमत से है तथा ऐसे मामलों में जहाँ निर्यात कीमत नहीं है अथवा जहाँ निर्यात कीमत निर्यातक तथा आयातक अथवा किसी तीसरे पक्षकार के बीच सहयोग अथवा प्रतिपूरक व्यवस्था के कारण विश्वसनीय नहीं है वहाँ निर्यात कीमत का परिकलन उस कीमत के आधार पर किया जा सकता है जिस कीमत पर पहले आयातित वस्तुओं की पहले एक स्वतंत्र क्रेता को पुनः बिक्री की जाती है अथवा उप- नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे उचित आधार पर इस स्थिति में आयातित वस्तु के रूप में पुनः बिक्री नहीं की जाती है;

36. प्राधिकारी ने निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली भेजी थी। संबद्ध देशों के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूएई के एकमात्र निर्यातक ने कीमत वचनबद्धता प्रस्तुत की है जिसके तहत निर्यातक उन कीमतों के नीचे, जिन्हें पहले अपाटित कीमत माना जाता था, की कीमत पर भारत को सामग्री का निर्यात नहीं करता था। अतः जिन कीमतों पर इस अवधि के दौरान निर्यात किए गए, उन्हें उन कीमत का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता जिन कीमतों पर कीमत वचनबद्धता के अभाव में निर्यात किए गए। फिर भी, प्राधिकारी ने वचनबद्ध कीमतों पर ऐसे निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए किए गए निर्यात की कीमत पर विचार करते हुए यूएई से किए गए निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है।

38. ईरान के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान ईरान से संबद्ध उत्पाद के कोई ज्ञात आयात नहीं हैं। अतः जांच अवधि के दौरान हुए निर्यातों के संबंध में वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

39. जांच प्रारंभ करते हुए प्राधिकारी ने निर्यातक देशों में भारतीय मिशनों का संगत सूचना एकत्रित करने की सलाह दी है। प्रस्तुत सूचना की जांच की गई थी, जिसका परिणाम निम्नानुसार है :-

(क) ईरान के संबंध में, निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई गई थी -

(i) सफेद सीमेन्ट के संबंध में वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2003-04 (ईरान के वित्त वर्ष के अनुसार) के लिए विभिन्न देशों को ईरान से सफेद सीमेन्ट के निर्यात। वर्ष 2004-05 के लिए सीमेन्ट क्लिंकर, ग्रे सीमेन्ट, एल्यूमीनियस सीमेन्ट तथा अन्य हाइड्रोलिक सीमेन्ट के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई गई है। भारतीय उत्पादकों ने वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा जुलाई, 2006-07 तक के लिए (ईरान के वित्त वर्ष के अनुसार) सफेद सीमेन्ट के निर्यातों के संबंध में भी सूचना उपलब्ध कराई है।

भारतीय दूतावास तथा घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की आगे और जांच की गई और यह पाया गया कि विचाराधीन उत्पाद का अनेक देशों को ऐसी कीमत पर काफी अधिक निर्यात किया जा रहा है, जो निर्धारित सामान्य मूल्य से कम है।

(ii) उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईरान के उत्पादक अनेक देशों में संबद्ध उत्पादों का पाटन कर रहे हैं तथा इन निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन उल्लेखनीय है।

(iii) ईरान के सफेद सीमेन्ट के उत्पादक द्वारा भारतीय दूतावास को कोटेशन दी गई थी, जो जांच अवधि की नहीं है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि ये बिक्री का प्रस्ताव है और चूंकि इस प्रस्ताव में इंगित कीमत में संक्षिप्त सीमाशुल्क आंकड़ों के अनुसार विभिन्न कीमतों के लिए औसत-कीमतों में अत्यधिक अंतर प्रदर्शित होता है, अतः इस सूचना को पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना का निर्धारण करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।

(iv) ईरान के व्यापार संवर्धन संगठन की स्थायी कीमत निर्धारण समिति द्वारा अनुसमर्थित निर्यात हेतु सीमेन्ट की मूल कीमत हेतु ऐसी कुछ कीमतें दर्शाई गई हैं जिन पर निर्यात किया जा सकता है। यद्यपि यह कीमत जांच अवधि के लिए नहीं है फिर भी यह पाया गया है कि इस दस्तावेज में उल्लिखित निर्यात कीमत, अनुमानित सामान्य मूल्य से कम है। अतः पाटनरोधी शुल्क को वापस ले लिए जाने की स्थिति में इस दस्तावेज में उल्लिखित कीमतों से, पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना भी प्रदर्शित होती है।

(ख) यूएई के मामले में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई गई थी।

(i) यूएई के एक उत्पादक ने ऐसी सूचना उपलब्ध कराई है जिससे निम्नलिखित की अभिपुष्टि होती है।

- क्षमता - 4,50,000 मी. टन
- वर्ष 2005 के दौरान उत्पादन - 3,11,686 मी. टन
- वर्ष 2005 में घरेलू खपत - 98,030
- वर्ष 2005 में निर्यात - 2,04,048 मी. टन

रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, संबद्ध कंपनी यूएई में सफेद सीमेन्ट की एकमात्र उत्पादक है। अतः यह निष्कर्ष निकाला गया था कि उपर्युक्त सूचना, यूएई के लिए संगत सूचना है। इसके अलावा, यद्यपि सूचना पूर्णतः जांच अवधि से संबद्ध नहीं है फिर भी प्राधिकारी ने इस सूचना को यूएई के पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ इस सूचना का उपयोग किया है।

(ii) प्राधिकारी ने वर्ष 2004 के लिए यूएई से विभिन्न देशों का निर्यातों के संबंध में व्यापार आंकड़े प्राप्त किए, जो निम्नानुसार हैं -

क्र. सं.	देश	मात्रा मी. टन
1	बेल्जियम	216
2	जर्मनी	231
3	हांगकांग	3,916
4	भारत	2,606
5	इंडोनेशिया	3,454
6	इराक	490
7	श्रीलंका	334
8	तुर्की	168
9	यूएसए	1,058
10	कुल	20,608

40. प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध वास्तविक साक्ष्य के आधार पर (क) विश्व भर की यूआई से निर्यात मात्रा (ख) जिस कीमत पर यूआई उत्पादक ने अन्य देशों एवं भारत का निर्यात किया है; के साथ इस सूचना की तुलना की है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यूआई से पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त सूचना उतनी उपयोगी नहीं है यद्यपि भारत दूतावास से प्राप्त इस सूचना से इस बात की पुष्टि होती है कि अन्य वैश्विक बाजारों में भी यूआई से निर्यात पाटित कीमतों पर किए गए हैं। उपलब्ध कराई गई सूचना में यूआई से निर्यातित मात्रा के केवल 10% को ही शामिल किया गया है।

41. याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध सरकारी प्राधिकारियों द्वारा संकलित सूचना के अनुसार निर्यातक देशों से निर्यातों के संबंध में भी साक्ष्य उपलब्ध कराया है। याचिकाकर्ता ने घरेलू खपत हेतु कुछेक प्रविष्टि बिल भी उपलब्ध कराए हैं, जिनमें विचाराधीन उत्पाद के आयातों को दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना निम्नानुसार है -

आधार	मात्रा	मूल्य	कीमत	अवधि
• डीजीसीआईएंडएस	0	0	0	जांच अवधि
• वास्तविक प्रविष्टि बिल	280	1282445	4580	दिसम्बर - 04
• निर्यातक देश के आंकड़े				
♦ 2004 कैलेण्डर वर्ष	2606	7867941	3019	2004
♦ 2005 कैलेण्डर वर्ष	4014	15898284	3961	2005

42. प्राधिकारी ने उपर्युक्त सूचना की भी जांच की है और पाया है कि ये कीमतें भी सामान्य मूल्य से कम हैं। यद्यपि, प्रविष्टि बिल से वे वचनबद्ध कीमतें प्रदर्शित होती हैं जिन पर निर्यात किए गए हैं, यद्यपि यह पाया गया है कि ये निर्यात पाटित कीमतों पर भी किए गए थे।

43. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमाशुल्क पत्तन प्राधिकारियों को भी संगत सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी है। एक सीमाशुल्क पत्तन से प्राप्त सूचना से 4580 प्रति मी. टन सीआईएफ की दर पर 280 मी. टन सफेद सीमेन्ट के आयात प्रदर्शित होते हैं।

(क) चूंकि यूआई से उत्पाद का आयात किया गया है अतः जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन का निर्धारण इन आयातों के आधार पर किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए आयातों की वास्तविक मात्रा, रिकॉर्ड में उपलब्ध आयात के साक्ष्यों से काफी अधिक है तथापि, निर्यात कीमत के संबंध में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। तथापि, प्राधिकारी ने सीमाशुल्क पत्तन प्राधिकारियों द्वारा यथाप्रमाणित, रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि बिल पर विचार करते हुए निर्यात कीमत की जांच की है, जिसमें यूआई के मामले में सकारात्मक पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वस्तुओं का निर्यात उस कीमत पर किया गया है, जिस कीमत पर निर्यातक ने पूर्व में कीमत वचनबद्धता की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्व में यह निर्धारित किया था कि उक्त कीमत उतनी थी जिस पर निर्यात, पाटित कीमत पर नहीं हों। अतः प्राधिकारी का मानना है कि वर्तमान जांच अवधि के दौरान जिस कीमत पर वस्तुओं का निर्यात किया गया है उसे पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु प्रतिनिधिक नहीं माना जा सकता।

(ख) ईरान के संबंध में कोई आयात सूचित नहीं किया गया है और इसलिए ईरान के लिए वास्तविक निर्यातों के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

(ग) यूएई के मामले में पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में प्राधिकारी ने उन कीमतों पर, जिस पर यूएई से बंगलादेश तथा कई अन्य देशों को वस्तुओं का निर्यात किया गया है, के संबंध में रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों पर विश्वास किया है। ईरान के मामले में प्राधिकारी ने (i) उन कीमतों पर जिनपर सीमाशुल्क आंकड़ों के अनुसार ईरान से कई अन्य देशों को वस्तुओं का निर्यात किया गया है, (ii) ईरान के व्यापार संवर्धन संगठन के स्थाई कीमत निर्धारण समिति द्वारा अनुसमर्थित, निर्यात की मूल कीमत पर विचार किया है।

(घ) उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ने निम्नानुसार पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है -

	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %
यूएई के मामले में	अम. डॉ.	अम. डॉ.	अम. डॉ.	
मूल जांच में	93.54	61.54	32.00	52.00
(I) वचनबद्ध कीमत पर वास्तविक लदान पर विचार करते हुए	118.10	88.00	30.10	34.20
(II) तीसरे देशों को निर्यात पर विचार करते हुए				
क) बंगलादेश (नवम्बर 05 के प्रविष्टि बिल के आधार पर)	118.10	48.00	70.10	146.04
ख) बंगलादेश (फरवरी, 2004 के प्रविष्टि बिल के आधार पर)	118.10	68.00	50.10	73.68
ग) इंडोनेशिया (इंडोनेशिया के सीमाशुल्क आंकड़ों के आधार पर - भारत औसत कीमत आधार)	118.10	68.88	49.22	71.46
भारत को निर्यातों पर विचार करते हुए				
घ) वर्ष 2004 के लिए भारत को निर्यातों के लिए भारतीय दूतावास के आंकड़ों पर विचार करते हुए	118.10	67.07	51.03	76.08
ङ.) घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्ष 2005 के लिए भारत को निर्यातों हेतु आंकड़ों पर विचार करते हुए	118.10	89.64	28.46	31.75
ईरान के मामले में				
मूल जांच में	86.43	40.20	46.23	115.00
(I) घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्ष 2005 के दौरान भारत औसत निर्यातों पर विचार करते हुए	118.10	60.48	57.62	95.27
(II) भारतीय दूतावास द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्ष 2003-04 के दौरान अन्य देशों को भारत औसत निर्यातों पर विचार करते हुए	118.10	55.04	63.06	114.57
(III) भारतीय दूतावास द्वारा उपलब्ध कराए गए ईरान की स्थायी कीमत निर्धारण समिति द्वारा अधिसूचित कीमत पर विचार करते हुए	118.10	64.00	54.10	84.53

प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यूएई के मामले में वास्तविक नौवहन के आधार पर निर्धारित पाटन मार्जिन इसलिए उपयोगी नहीं है क्योंकि निर्यात कीमत वचनबद्ध कीमत की प्रतिनिधिक कीमत हैं।

तीसरे देशों को निर्यातों पर आधारित पाटन मार्जिन 71 - 146% के बीच में है। ईरान के मामले में, तीसरे देशों को निर्यातों के आधार पर निर्धारित पाटन मार्जिन 85- 115% के बीच में थे। इन निर्धारणों से जहाँ यह निर्धारित होता है कि पाटनरोधी शुल्कों को वापस ले लिए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना है, वहीं प्राधिकारी का यह मानना है कि पाटनरोधी शुल्कों की मात्रा के निर्धारण के प्रयोजनार्थ पाटन मार्जिन की इन मात्राओं को उपयोग में लाना उचित नहीं होगा। चूंकि मूल जांच के समय पाटन मार्जिन मूल जांच के समय का निर्धारण भारत को वास्तविक नौपरिवहन के आधार पर किया गया था, अतः वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच की प्रकृति के हैं तथा वास्तविक नौवहन वचनबद्ध कीमत पर किए गए थे। चूंकि संगत अवधि के दौरान भारत को कोई निर्यात नहीं किए गए थे, अतः प्राधिकारी का मानना है कि वर्तमान जांच में पाटनरोधी शुल्कों की मात्रा के निर्धारण के प्रयोजनार्थ पाटन मार्जिन का निर्धारण मूल जांच के समय किया गया मानना उचित होगा अर्थात् यूएई के मामले में 32.00 अम. डॉ. (52.00%) तथा ईरान के मामले में 46.23 अम. डॉ. (115.00%)।

पाटन की संभावना के संबंध में, भारत को निर्यातित सीमेंट क्लिंकर्स की कीमत पर विचार करते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमेंट क्लिंकर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। चूंकि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में उत्पाद को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना के निर्धारण हेतु सीमेंट क्लिंकर की आयात कीमत का प्रयोग करना उचित नहीं है।

च.5. पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

45. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटन को निष्प्रभावी करने के लिए शुल्क को लागू रखना आवश्यक है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया है :-

(क) मूल जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन

(ख) वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन - जांच अवधि के दौरान जब भी भारत को निर्यात किए गए थे उन पर विचार किया गया था और पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया था।

(ग) प्राधिकारी ने अन्य देशों को निर्यातित वस्तुओं की कीमत पर विचार करते हुए पाटन की संभावना का निर्धारण किया है।

(घ) विदेशी उत्पादकों द्वारा किए गए ज्ञात विस्तारों को ध्यान में रखते हुए मुक्त रूप से निपटान योग्य वर्तमान और संभावित क्षमताएं, भारत में प्रचलित कीमतें, निर्यातों की वास्तविक एवं संभावित मात्रा, इन देशों से अन्य देशों को किए गए निर्यात की कीमत।

46. इन कारकों की जाँच करने पर यह नोट किया जाता है कि

(क) किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच का उत्तर नहीं दिया है। यह दर्शाया नहीं गया है कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति होगी और पाटन की क्षतिपूर्ति हेतु शुल्क को जारी रखना अनावश्यक है। प्राधिकारी ने आगे की जांच सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना/उपलब्ध तथ्य के आधार पर की है।

(ख) यूएई के निर्यातक मै. आर. ए. के. द्वारा की गई कीमत वचनबद्धता के आधार पर यह सिद्ध होता है कि यदि कीमत वचनबद्धता की समयावधि समाप्त होती है तो यूएई से पाटित कीमतों पर निर्यात किए जाएंगे। अतः यदि लागू पाटनरोधी शुल्क की अवधि समाप्त होती है तो यूएई से पाटित कीमतों पर निर्यात किए जाने की संभावना है।

(ड.) यूएई के उत्पादक के पास काफी मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताएं हैं। उत्पादक के पास न केवल काफी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं बल्कि वह विभिन्न देशों को काफी मात्रा में निर्यात भी कर रहा है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि इन निर्यातों का गंतव्य उत्पादक को इनसे प्राप्त कीमत पर निर्भर करता है।

(च) दुबई पत्तन के जरिए निर्यात के संबंध में संकलित आंकड़ों में 23,625 मी. टन के निर्यात दर्शाए गए हैं; जबकि मै. आर. ए. के. ने यह स्वीकार किया है कि कंपनी 2,04,048 मी. टन का निर्यात कर रही है। आर. ए. के. द्वारा उस कीमत के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है जिसपर 2,04,048 मी. टन का निर्यात किया गया है। इस संबंध में, कोई सूचना प्रकाशित भी नहीं की गई है। तथापि, आर. ए. के. द्वारा प्रदत्त सूचना में भारी मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताओं की मौजूदगी स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है।

(छ) यूएई के उत्पादक ने अन्य देशों को काफी भिन्न-भिन्न कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। दो वर्ष से कम पहले के एक मामले में बांग्लादेश को किए गए निर्यातों की कीमतों में 20 अम. डा. पीएमटी का भारी अंतर था (जो उत्पादन की संबद्ध लागतों में किसी खास परिवर्तन के न होने को देखते हुए काफी अधिक है)। इस प्रकार निर्यातक जिन कीमतों पर सामग्री को बेचना चाहता है, वे काफी अलग-अलग हैं।

(ज) बांग्लादेश को वस्तुओं का निर्यात काफी पाटित कीमतों पर किया गया है।

(झ) यूएई के उत्पादक ने भारत को वचनबद्धता कीमत के लगभग समान कीमतों पर निर्यात किया है। अतः यह स्पष्ट है कि यदि वर्तमान शुल्क को हटाया जाता है तो निर्यातक अपनी कीमतों में काफी कमी कर सकता है (वर्तमान शुल्कों की समाप्ति से कीमत वचनबद्धता भी समाप्त हो जाएगी)।

(ञ) विभिन्न देशों को यूएई के निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन में काफी भिन्नताएं हैं, इस प्रकार इनसे पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में और अधिक पाटन होने की संभावना सिद्ध होती है।

(ट) ईरान के उत्पादक उत्पाद का निर्यात स्थाई कीमत निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित या अनुसमर्थित निर्यात की मूलभूत कीमत पर कर रहे हैं। इस प्रकार तय की गई कीमतें सामान्य मूल्य के अनुमानों से काफी कम हैं। यदि यह माना जाता है कि इन कीमतों पर भारत को निर्यात किए जाएंगे तो यह स्पष्ट है यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो पाटन की पुनरावृत्ति होगी।

(ठ) जैसाकि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है और किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उस पर आपत्ति नहीं की गई है, ईरान तथा यूएई में सफेद सीमेंट की उत्पादन क्षमता, उत्पादन, माँग और खपत निम्नानुसार है :-

	ईरान	यूएई
क्षमता	929835	450000
उत्पादन	759251	311686
घरेलू माँग	420000	98030
निर्यात	339251	204048
अप्रयुक्त क्षमता	170584	138314

(ड) प्राधिकारी यह देखते हैं कि दोनों देशों में काफी अप्रयुक्त क्षमताएं मौजूद हैं। इसके अलावा, दोनों देश अनेक देशों को निर्यात कर रहे हैं और इसलिए किसी तीसरे देशों के निर्यातों को भारत में स्थानांतरित करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है।

सफेद सीमेंट के निर्यातों के अलावा, यह नोट किया जाता है कि इन देशों से क्लिंकर का निर्यात किया जाता है। फिर भी यद्यपि क्लिंकर को शामिल करके विचाराधीन उत्पाद के दायरे में विस्तार करना उचित नहीं होगा और न ही यह उचित होगा कि क्लिंकर के आयातों को विचाराधीन उत्पाद का आयात माना जाए, तथापि, यह स्पष्ट है कि निर्यातक क्लिंकर के बजाय सफेद सीमेंट का निर्यात करने को तरजीह देंगे। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में पाटन की संभावना में निर्धारण हेतु निर्यातों की मात्रा तथा वह कीमतें जिन पर निर्यात किए जा रहे हैं, भी संगत कारक हैं। उन कीमतों जिन पर क्लिंकर का निर्यात किया गया है तथा क्लिंकर के बाद शामिल मूल्यवर्धन पर विचार करने पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में निर्यातकों द्वारा पर्याप्त पाटित कीमतों पर क्लिंकर के बजाय सफेद सीमेंट का निर्यात किए जाने की संभावना है।

(ग) अनेक देशों को संबद्ध देश से निर्यात कीमत न केवल सामान्य मूल्य से काफी कम है बल्कि यह भारत में प्रचलित बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमत से भी कम है;

प्राधिकारी ने उस कीमत पर विचार करते हुए पाटन की संभावना का निर्धारण किया है जिस पर अन्य देशों को वस्तुओं का निर्यात किया गया है। इस प्रयाजनार्थ संबद्ध निर्यातकों के असहयोग की दृष्टि से प्राधिकारी ने अन्य देशों को निर्यातित वस्तु की कीमत के संबंध उपलब्ध सूचना पर विचार किया है।

निर्यातकों द्वारा यह दर्शाया नहीं गया है कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना होगी तथा पाटन को निष्प्रभावी करने के लिए शुल्क को लागू रखना अनावश्यक है।

(ड.) संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों की अत्यधिक अधिशेष अप्रयुक्त क्षमता और कीमत में काफी अंतर को देखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर भारी मात्रा में भारत को निर्यात किए जाने की संभावना है। क्षमता, उत्पादन, बिक्री, माँग और कीमतों से संबंधित साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि पाटनरोधी शुल्क हटाने से पुनः या अत्यधिक पाटन होगा और इस पाटन को निष्प्रभावी करने के लिए शुल्क लागू रखना आवश्यक है। रिकॉर्ड में रखे साक्ष्यों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने से संबद्ध देशों से पाटन की पुनरावृत्ति होगी।

छ. क्षति निर्धारण की पद्धति और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि ये पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है इसलिए घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के जारी रहने और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के वास्तविक एवं संभावित आयातों के संदर्भ में किए जाने की आवश्यकता है।

छ.1. क्षति जारी रहना

48. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इन तर्कों को नोट किया है कि निर्णायक समीक्षा जांच में क्षति एवं कारणात्मक संबंध का निर्धारण करना अनिवार्य नहीं है। तथापि, जांच अवधि के दौरान यूआई से निर्यातित

संबद्ध वस्तु के लिए निर्धारित सकारात्मक पाटन मार्जिन और ईरान तथा यूएई से संभावित पाटन के निर्धारण में प्राधिकारी ने इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति, यदि कोई हो, की भी जांच की है। अतः प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को उस अवधि के दौरान क्षति हुई है जब पाटनरोधी शुल्क लागू था।

उ.2. घरेलू उद्योग के विचार

49. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि :

(i) निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी के लिए एडीए के अनुच्छेद 3 और नियमावली के अनुबंध - II की अपेक्षाओं से प्रतिबंधित होना अपेक्षित नहीं है और समीक्षा जांच में कारणात्मक संबंध की जांच करना अपेक्षित नहीं है। ओटीसीजी के मामले में डब्ल्यूटीओ के निर्णय का संदर्भ दिया गया है और इन पर विश्वास किया गया है।

(ii) निर्णायक समीक्षा जांच में, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार प्रदर्शित होने की स्थिति में प्राधिकारी के लिए शुल्क को हटाए जाने के मामले में क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करना अपेक्षित है। यदि यह माना भी जाता है कि समीक्षा अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को लगातार वास्तविक क्षति नहीं हुई है तब भी यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग की सकारात्मक स्थिति में व्यवधान उत्पन्न होगा। इसके अलावा, क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की जांच किए बिना केवल घरेलू उद्योग की सकारात्मक स्थिति लागू शुल्क को हटाए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय द्वारा अमरीका - अर्जेंटीना से ऑयल कंट्री ट्यूबलर गुड्स पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के मामले में यही विचार व्यक्त किया गया है।

(iii) घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है जैसाकि भारी सकारात्मक कीमत कटौती, संबद्ध देशों में विदेशी उत्पादकों के पास उपलब्ध अत्यधिक मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताओं, भारतीय बाजारों की आकर्षक कीमतें (अन्य तीसरे देश के बाजार की तुलना में भारतीय बाजार की उच्चतर कीमतें) संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा तीसरे देश के बाजार में पाटन से सिद्ध होता है। वर्तमान मामले में आंकड़ों/सूचना के विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। दूसरे शब्दों में पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को प्रतिकूल मात्रा संबंधी क्षति और कीमत संबंधी क्षति दोनों की संभावना है। घरेलू उद्योग ने लागू शुल्क की समयावधि समाप्त होने की स्थिति में संभावित मात्रात्मक क्षति और संभावित कीमत संबंधी क्षति को संख्यात्मक रूप में दर्शाया है।

(iv) वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन पर कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि शुल्क लागू है और आयात सीमित है। तथापि, (1) संबद्ध देशों में अतिरेक क्षमता (2) विशाल भारतीय बाजार (3) भारतीय बाजार की आकर्षक कीमतों (4) तीसरे देश के पाटन का देखते हुए शुल्क को हटाए जाने की स्थिति में आयातों में वृद्धि होने की संभावना है।

(v) चूंकि कीमत वचनबद्धता विद्यमान है, इसलिए यूएई के उत्पादक द्वारा पहले की गई वचनबद्धता से सहमत कीमत पर भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जा रहा था। इसका यह अर्थ नहीं है कि घरेलू उद्योग की स्थिति पर किसी संभावित प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नहीं है। चूंकि वर्तमान निर्यात वचनबद्ध

कीमतों पर किए गए हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से वर्तमान निर्यातों का घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल कीमत प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि, यदि वर्तमान शुल्क को हटाया जाता है तो यह स्पष्ट है कि कीमत वचनबद्धता भी समाप्त हो जाएगी। यदि वर्तमान शुल्क के साथ वर्तमान कीमत संबंधी वचनबद्धता वापस ली जाती है तो यह स्पष्ट है कि यूएई के निर्यातों से घरेलू उद्योग पर अत्यधिक प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ेगा।

(vi) विदेशी उत्पादकों की वर्तमान क्षमता पहले ही निर्यातक देश में माँग से अधिक है। क्षमताएं अभी भी अप्रयुक्त हैं। इसके अलावा नई क्षमताएं भी स्थापित की गई हैं। यूएई के उत्पादक की क्षमता एवं माँग निम्नानुसार हैं -

विवरण	इकाई	मात्रा	
मुक्त रूप से निपटान योग्य अधिशेष क्षमता	मी. टन	3,30,000	
भावी विस्तार	मी. टन	1,50,000	
माँग के % के रूप में वर्तमान अतिरेक क्षमता	%	175%	
माँग के % के रूप में संभावित अतिरेक क्षमता	%	400%	

(vii) तटवर्ती क्षेत्र में स्थित घरेलू उद्योग निम्नांकित तालिकानुसार बिक्रियों का लाभ उठा रहा है जिसे वह शुल्क हटाए जाने की स्थिति में गँवा देगा। ऐसा इसलिए है कि विदेशी उत्पादकों के पास काफी अधिक अप्रयुक्त क्षमता है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग ने केवल तटवर्ती क्षेत्र हेतु पाटन के प्रभाव को सीमित करने पर विचार करते हुए बिक्रियों में संभावित हानि का आकलन किया यद्यपि यह तर्क दिया गया था कि पाटन तटवर्ती क्षेत्र तक सीमित नहीं था।

तटवर्ती क्षेत्र	जाँच अवधि में बिक्रियाँ
केरल	*****
तमिलनाडु	*****
महाराष्ट्र	*****
गुजरात	*****
पश्चिम बंगाल	*****
कर्नाटक	*****
आंध्र प्रदेश	*****
उड़ीसा	*****
पाँडिचेरी	*****
कुल बिक्रियाँ	299,624

(viii) संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर निर्यातों की अत्यधिक मात्रा से घरेलू उद्योग को बिक्रियाँ में घाटे के विकल्प के रूप में भारतीय घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत घटाने पर बाध्य या मजबूर होना पड़ेगा। संभावित कीमतें नीचे तालिका में दर्शाई गई हैं। निम्नांकित तालिका में आयातों की निवल बिक्री प्राप्तियों और पहुँच कीमत के बीच तुलना की गई है :-

		इकाई	कीमत प्रभाव	मात्रात्मक प्रभाव
			यदि कीमत में कमी की जाती	यदि कीमत में कमी नहीं की जाती
1	संबद्ध देश में क्षमता	मी. टन	1,380,000	1,380,000
2	संबद्ध देशों में माँग		540,000	540,000
3	निर्यातक देश में अधिशेष क्षमता	मी. टन	840,000	840,000

4	संबद्ध देशों में उत्पादन	मी. टन	1,140,000	1,140,000
5	निर्यातक देश में अप्रयुक्त अधिशेष क्षमता	मी. टन	240,000	240,000
6	अधिशेष उत्पादन	मी. टन	600,000	600,000
7	ईष्टतम क्षमता उपयोग	%	85	85
8	संभावित अधिशेष उत्पादन	मी. टन	633,000	633,000
9	भारत में माँग	मी. टन	550,000	550,000
10	घरेलू उद्योग का उत्पादन	मी. टन	562,885	263,261
11	घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	509,450	209,826
12	तटवर्ती क्षेत्र में घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	299,624	-
13	घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग	%	72.63	33.97
14	सीआईएफ कीमत, यदि शुल्क हटाया जाता है	अम. डॉलर मी. टन	80	80
15	सीआईएफ कीमत, यदि शुल्क हटाया जाता है	रु./ मी. टन	3,600	3,600
16	मूल शुल्क सहित पहुँच कीमत	रु./ मी. टन	4,181	4,181
17	घरेलू उद्योग का वर्तमान बिक्री कीमत	रु./ मी. टन	*****	*****
18	घरेलू उद्योग की संभावित बिक्री कीमत	रु./ मी. टन	*****	*****
19	घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत	रु./ मी. टन	*****	*****
20	लाभ/हानि	रु./ मी. टन	*****	*****
21	संभावित लाभ/हानि	रु./ मी. टन	*****	*****
22	घरेलू बिक्री पर वर्तमान लाभ हानि	लाख रु.	*****	*****
23	कुल बिक्रियों पर होने वाला लाभ/हानि	लाख रु.	*****	*****
24	वर्तमान नकदी प्रवाह	लाख रु.	*****	*****
25	संभावित नकदी प्रवाह	लाख रु.	*****	*****
26	वर्तमान आरओई	%	15.66	15.66
27	संभावित आरओई	%	(15.64)	(15.64)

(ix) अतः घरेलू उद्योग को कम हो रही बिक्री मात्राओं और कीमतों में कमी के बीच एक को चुनना होगा। यदि घरेलू उद्योग कीमतें समान करने को तरजीह देता है तो कीमत में कमी बहुत अधिक होगी।

छ.3 निर्यातक/आयातक/अन्य हितबद्ध पक्षकार के विचार

50. अन्य हितबद्ध पक्षकारों में से किसी ने भी इस संबंध में कोई तर्क/निवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

छ.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

51. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की वास्तविक क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई विभिन्न दलीलों को नोट किया है।

52. प्राधिकारी ने शुल्क वापस लिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि निर्यातक द्वारा दी गई कीमत वचनबद्धता के आधार पर प्रारंभ में मै0 आर ए के, यू ए ई पर शुल्क नहीं लगाया गया था। वर्तमान जांच सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार शुरू की गई है जिसमें प्राधिकारी के लिए यह निर्धारण करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क को पांच वर्ष की आगे की अवधि के लिए जारी रखना अपेक्षित है और जांच के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना और उनके द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर संभावित पाटन एवं क्षति की मात्रा एवं सीमा तथा शुल्क जारी रखने अथवा शुल्क हटाने की जरूरत की जांच करना भी अपेक्षित है।

53. जांच अवधि में वर्तमान क्षति के आकलन के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर मात्रा एवं कीमत संबंधी प्रभावों की जांच की है। यू ए ई के मामले में सकारात्मक पाटन मार्जिन और प्रत्येक संबद्ध देश से महत्वपूर्ण स्तरों पर पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना स्थापित की गई है।

मांग एवं बाजार हिस्से का आकलन

54. मांग एवं बाजार हिस्से के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्रियों और विभिन्न स्रोतों से आयातों पर विचार किया था। भारत में उत्पाद की मांग की गणना भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और विभिन्न देशों से ज्ञात आयातों के योग के रूप में की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदान की गई सूचना में किए गए आयात की पूरी मात्राएं प्रदर्शित नहीं हुई हैं। इस प्रकार आकलित मांग को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

	इकाई	2002-03	2003-04	2004-05	POI
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	503,120	535,815	526,507	539,860
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100.00	106.50	104.65	107.30
डी जी सी आई एंड एस के आयात - यू ए ई और ईरान को छोड़कर	मी.टन	2	70	0	0
आयात डी जी सी आई एंड एस - ईरान	मी.टन	2	0	0	0
आयात अन्य साक्ष्य यू ए ई	मी.टन	1,203	2,671	2958	3,662
कुल आयात	मी.टन	1207	2741	2958	3,662
मांग	मी.टन	504327	538556	529465	543522
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100.00	106.79	104.98	107.77

55. यह देखा जाता है कि संबद्ध वस्तु की मांग में क्षति अवधि के दौरान एक सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। जांच से पता चला है कि यदि इस अवस्था में पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाते हैं तो यू ए ई और ईरान के निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा पाटित कीमतों पर पुनः निर्यात शुरू किए जाने की संभावना है।

मात्रा संबंधी प्रभाव

56. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन की तुलना में वास्तविक अथवा संभावित वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II (ii) में निम्नानुसार प्रावधान है:

'पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों के समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में पर्याप्त वृद्धि हुई है।'

57. इस अवधि के दौरान आयातों की वास्तविक मात्रा निम्नानुसार रही है:-

	इकाई	2002-03	2003-04	2004-05	POI
आयात मात्रा					
यू ए ई	मी.टन	1,203	2,671	2958	3,662
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100.00	221.95	245.80	304.30
ईरान	मी.टन	2	0	0	0
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100.00			
अन्य देश	मी.टन	2	70	0	0
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100.00	3500		
कुल आयात	मी.टन	1207	2741	2958	3,662
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100.00	227.01	244.99	303.30
आयातों में बाजार हिस्सा					
यू ए ई	%	99.67	97.45	100.00	100.00
ईरान	%	0.17	-	-	-
अन्य देश	%	0.17	2.55	0	0
मांग में बाजार हिस्सा					
यू ए ई	%	0.24	0.50	0.56	0.67
ईरान	%	0	0	0	0
अन्य देश	%	0	0.01	0	0
भारतीय उत्पादन के संबंध में आयात					
यू ए ई	%	0.22	0.49	0.52	0.63
ईरान	%	0.00	-	-	-
अन्य देश	%	0.00	0.01	-	-

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि आयातों की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में कुछ वृद्धि हुई है लेकिन आयातों की मात्रा उस समय बहुत कम है जब इस पर भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में विचार किया गया। तथापि, उपलब्ध साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में आयातों की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है।

कीमत संबंधी प्रभाव

59. पाटित आयातों के कीमत पर प्रभाव की संबंध में नियमावली के अनुबंध II (ii) में निम्नानुसार विनिर्दिष्ट है:-

"नियम 18 के उप-नियम (2) में यथा संदर्भित पाटित आयातों के कीमत पर प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को एक महत्वपूर्ण सीमा तक कम करना अथवा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण सीमा तक हो गई होती।"

60. किसी निर्णायक समीक्षा जांच में यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत संबंधी अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था अथवा क्या पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने के मामले में कीमत संबंधी अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

61. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली का निर्धारण करें एवं शुल्कों, छूटों, कटौतियों को छोड़कर परिवहन सहित बिक्री कीमत पर विचार करके किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की समस्त बिक्री मात्राओं पर विचार किया गया है। आयातों की पहुँच कीमत का निर्धारण 1 प्रतिशत पतन प्रभार और लागू मूल सीमाशुल्क के साथ भारत औसत सी आई एफ आयात कीमत पर विचार करके किया गया है। सफेद सीमेंट की निवल बिक्री वसूली और आयातों की पहुँच कीमत के बीच तुलना की जाती है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु हेतु पाटित आयातों के भारत औसत पहुँच मूल्य और परिवहन सहित घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई थी।

रूप प्रति मी.टन	यू ए ई	ईरान
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली	*****	*****
पहुँच मूल्य	5,150	-
कीमत कटौती	*****	-
कीमत कटौती (%)	13-15%	-

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि आर ए के से वर्तमान निर्यात कीमत वचनबद्धता और निर्यातों के अंतर्गत किए गए थे और अन्य निर्यातकों द्वारा कोई निर्यात नहीं किए गए हैं, इसलिए जिस कीमत पर वर्तमान निर्यात किए गए हैं वह पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में संभावित कीमतों की पर्याप्त सूचक नहीं है। यह नोट किया जाता है कि उस कीमत पर जिस पर वस्तु का अन्य देशों को निर्यात किया गया है, के मद्देनजर संभावित भावी कीमतें अत्यधिक कम हो सकती हैं। अतः यह पाया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में आयातों से अत्यधिक कीमत कटौती होने की संभावना है और संभावित कीमत 9 प्रतिशत से 47 प्रतिशत के पराश में होगी।

63. प्राधिकारी ने यह भी निर्धारण किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा कम कीमत पर बिक्री का सामना किए जाने की संभावना है। इस प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने यू ए ई से वास्तविक और संभावित कीमतों तथा ईरान से संभावित कीमतों पर विचार किया और इसकी क्षतिरहित कीमत के साथ तुलना की।

रूप प्रति मी. टन	वर्तमान	
	यू ए ई	ई स न
घरेलू उद्योग हेतु क्षतिरहित कीमत	*****	*****
पहुँच मूल्य	5,150	
कम कीमत पर बिक्री	*****	
कम कीमत पर बिक्री (%)	30-32%	

64. कम कीमत पर बिक्री की सीमा का पता लगाने के लिए घरेलू उद्योग हेतु निर्धारित क्षति रहित कीमत की पहुँच मूल्य के साथ तुलना की गई थी। घरेलू उत्पादकों हेतु क्षति रहित कीमत का मूल्यांकन जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत पर उपयुक्त रूप से विचार करके और लगाई गई पूँजी पर उचित लाभ प्रदान करके किया गया है। विश्लेषण से पता चलता है कि संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से संबद्ध वस्तु की संभावित पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से बहुत कम है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कम कीमत पर बिक्री संबंधी संभावित मार्जिनों की भी जाँच की है। कम कीमत पर बिक्री संबंधी संभावित मार्जिन जाँच अवधि के दौरान 9 से 47 प्रतिशत के पराश में थे।

घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड

65. नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में इन आयातों का संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जाँच शामिल होगी। इसके अलावा, नियमावली के अनुबंध II (iv) में बिक्रियों में वास्तविक अथवा संभावित कमी, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर आय अथवा क्षमता उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, मालसूचियों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारक और संकेतक निर्धारित किए गए हैं।

क्षमता, उत्पादन, बिक्रियां और क्षमता उपयोग

66. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्राओं के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार रही है:-

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
क्षमता	730,000	730,000	775,000	805,000
सूचीबद्ध	100.00	100.00	106.16	110.27
उत्पादन	537,257	549,239	563,814	584,104
सूचीबद्ध	100.00	102.23	104.94	108.72
क्षमता उपयोग	73.60	75.24	72.75	72.56
सूचीबद्ध	100.00	102.23	98.85	98.59
घरेलू बिक्रियां	501,815	532,343	519,403	530,629
सूचीबद्ध	100.00	106.08	103.50	105.74

67. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि पाटित आयातों से अत्यधिक कीमत कटौती होने की संभावना है और संबद्ध विदेशी उत्पादकों के पास अत्यधिक मुक्त

रूप से प्रयोज्य क्षमताओं के मद्देनजर इस बात की संभावना है कि घरेलू उद्योग या तो बिक्री मात्राएं गंवा देगा अथवा पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में कीमतें कम करने के लिए बाध्य होगा। यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें बनाए रखने को तरजीह देता है तो यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग बिक्री मात्राएं गंवा देगा और परिणामस्वरूप इसके उत्पादन और क्षमता उपयोग को क्षति होगी।

उत्पादकता

68. घरेलू उद्योग की उत्पादकता निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
प्रति कर्मचारी उत्पादकता (मी.टन)	*****	*****	*****	*****
उत्पादकता की प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100.00	101.14	102.99	105.24

69. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाते हैं तो उत्पादकता में कमी होगी।

मांग में बाजार हिस्सा

70. मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
मांग में बाजार हिस्सा				
घरेलू उद्योग	99.76	99.49	99.44	99.33
संबद्ध देश	0.24	0.50	0.56	0.67
अन्य देश	0.00	0.01	0	0

71. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने में सक्षम रहा है। तथापि यह नोट किया जाता है कि यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों को हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आएगी।

लाभ, निवेश पर आय और नकदी प्रवाह

72. घरेलू उद्योग के लाभ, निवेश पर आय और नकदी प्रवाह की वर्तमान और संभावित स्थिति की जांच की गई है। घरेलू उद्योग के इन मानदंडों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार रही है:

लाभ में	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
कर पूर्व लाभ	*****	*****	*****	*****
सूचीबद्ध	100.00	66.30	50.86	77.90
लगाई गई पूंजी पर आय - जी एफ ए आधार	22.10	16.71	11.90	14.82
सूचीबद्ध	100.00	75.60	53.83	67.06
लगाई गई पूंजी पर आय - एन एफ ए आधार	34.33	26.82	14.94	19.15
सूचीबद्ध	100.00	78.12	43.53	55.77
नकद लाभ	*****	*****	*****	*****
सूचीबद्ध	100.00	73.20	62.52	87.99

73. यह नोट किया जाता है कि लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकदी प्रवाह में क्षति अवधि के दौरान गिरावट प्रदर्शित हुई है। इसके अलावा, कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के स्तर जो पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में आयातों के कारण होगा, के मद्देनजर इन मानदंडों के संबंध में संभावित स्थिति में भी अत्यधिक गिरावट प्रदर्शित हुई है। यदि घरेलू उद्योग आयात कीमतों के बराबर कीमतों पर बिक्री कर रहा है तो यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को अत्यधिक वित्तीय घाटा, निवेशों पर नकारात्मक आय और नकारात्मक नकदी प्रवाह का सामना करना पड़ेगा।

रोजगार और मजदूरी

74. रोजगार और मजदूरी से संबंधित सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है। यह देखा जाएगा कि रोजगार और मजदूरी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

	इकाई	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
रोजगार	सं०	*****	*****	*****	*****
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100.00	101.08	101.89	103.31
मजदूरी	लाख रुपये	*****	*****	*****	*****
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100.00	114.01	116.71	119.66

मालसूचियां

75. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के मालसूची स्तर की जांच की है जो निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

एमटी	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
वस्तु सूची	16,785	17,006	16,082	16,943
सूचीबद्ध	100.00	101.32	95.81	112.86
घरेलू बिक्री के % के रूप में वस्तु सूची	3.34	3.17	3.05	3.51
सूचीबद्ध	100.00	95.13	91.55	105.18

76. घरेलू उद्योग की वस्तु सूची के स्तर में बढ़ोतरी हुई है, तथापि यह उल्लेखनीय नहीं है।

वृद्धि

77. घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानदण्डों की जांच के उपरांत यह नोट किया गया कि मात्रा तथा कीमत से संबंधित घरेलू उद्योग के मानदण्ड सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाते हैं, जो संबद्ध देश के विरुद्ध लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के कारण है। तथापि पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाने की स्थिति में आयातों की मात्रा व कीमत पर पड़ने वाले सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव के कारण यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाने पर घरेलू उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

पाटन की सीमा

78. यह नोट किया गया है कि पाटन मार्जिन, निर्धारित सीमा से अधिक तथा उल्लेखनीय स्तर पर है। निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है :-

मूल जांच में यथा निर्धारित	
➤ यूएई	52%
➤ ईरान	115%
वर्तमान जांच में निर्धारित	
यूएई	
➤ वचनपत्र कीमत पर वास्तविक पोतलदान के अनुसार	34.20%
➤ तीसरे देश-बांग्लादेश को निर्यात के अनुसार	146.04 %
➤ तीसरे देश - बांग्लादेश को निर्यात के अनुसार	73.68%
➤ इंडोनेशिया - इण्डोनेशिया के सीमाशुल्क आंकड़ों के आधार पर - औसत कीमत	71.46%
वर्ष 2004 के लिए भारत को किए गए निर्यात के संबंध में भारतीय दूतावास के आंकड़ों के अनुसार	76.08 %
वर्ष 2005 के लिए भारत को किए गए निर्यात के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार	31.75%
ईरान	
➤ वर्ष 2005 में अन्य देशों को किए गए भारत औसत निर्यात के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार	95.27%
➤ भारतीय दूतावास की सूचना के आधार पर वर्ष 2003-2004 के दौरान तीसरे देशों को भारत औसत निर्यात के अनुसार	114.57. %
➤ भारतीय दूतावास की सूचना के आधार पर ईरान की स्थायी कीमत निर्धारण समिति द्वारा अधिसूचित कीमत के अनुसार	84.53. %

यह स्पष्ट है कि जब भी निर्यात किया गया है, यह उल्लेखनीय पाटित कीमतों पर किया गया है ।

पूंजी तथा निवेश जुटाने की क्षमता

79. यह नोट किया जाता है कि प्रचलित पाटनरोधी शुल्क तथा इस तथ्य के मद्देनजर, कि दोनों कम्पनियां बहु-उत्पाद कम्पनियां हैं, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । तथापि यह नोट किया जाता है कि जे.के. व्हाइट अब वर्तमान उत्पाद के व्यवसाय में है और किसी भी दीर्घावधिक दुष्प्रभाव से कम्पनी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

80. घरेलू बाजार में कीमतों पर प्रभाव पड़ने वाले पाटित आयातों से इतर सम्भावित कारकों के विश्लेषण हेतु लागत संरचना में परिवर्तन, यदि कोई हो, तथा घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण किया गया । यह नोट किया गया कि सम्बद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत से काफी कम रहने की सम्भावना है, और इससे भारतीय बाजार में उल्लेखनीय कीमत कटौती होने की सम्भावना है । यह भी नोट किया गया है कि इस उत्पाद का कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं है और आयातित वस्तुओं के पहुँच मूल्य के साथ-साथ घरेलू कीमतों में भी आपसी प्रतिस्पर्धा होती रहती है । उत्पाद के स्वरूप को देखते हुए यदि आयातित उत्पाद घरेलू उत्पाद की तुलना में बहुत सस्ता है, तो घरेलू उत्पाद आयातित उत्पाद से प्रतिस्थापित अवश्य होगा ।

81. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दर्शाता है कि बाजार में जब भी आयात की सूचना प्राप्त हुई है, घरेलू उद्योग ने इसकी कीमतों पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है । ऐसी स्थिति में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाने पर बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ।

क्षति की सीमा तथा क्षति मार्जिन

82. क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित परिवहन लागत सहित क्षति रहित कीमत की तुलना आयातों के पहुँच मूल्य से की गई। भारत औसत क्षति मार्जिन उल्लेखनीय पाई गई है।

अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संबंध

83. घरेलू उद्योग ने तर्क प्रस्तुत किया है कि निर्णायक समीक्षा के सन्दर्भ में पाटनरोधी अधिनियम की धारा 3.3 की शर्तें लागू नहीं होतीं।

84. इस बात के होते हुए भी प्राधिकारी द्वारा क्षति की सम्भावना और संबद्ध देशों से पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध की जांच की गई। प्राधिकारी द्वारा जांच की गई कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है अथवा क्षति की सम्भावना हो सकती है।

अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा तथा कीमतें

85. यह नोट किया गया है कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के कोई ज्ञात आयातक नहीं है। केवल यूएई द्वारा ही यह सामग्री भारत को निर्यात की जा रही है, और भारत में उत्पादन/खपत की दृष्टि से इसकी मात्रा उल्लेखनीय नहीं हैं और यह भी नोट किया गया है कि ईरान के मामले में यदि पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिया जाए तो भारत को सम्बद्ध वस्तुओं के निर्यात की सम्भावना बहुत अधिक होगी।

	इकाई	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
आयातों की मात्रा					
➤ यूएई	मि.टन	1,203	2,671	2958	3,662
➤ ईरान	मि.टन	2	70	-	-
➤ अन्य देश	मि.टन	2	0	0	0
कुल आयात	मि.टन	1207	2741	2958	3,762

मांग में संकुचन एवं/अथवा खपत के तरीके में परिवर्तन

86. यह नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में नकारात्मक वृद्धि नहीं हुई। इस प्रकार मांग में संकुचन वह सम्भावित कारण नहीं है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

	इकाई	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
मांग	मि.टन	504327	538556	529465	543522
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100.00	106.79	104.98	107.77

87. खपत के तरीके में परिवर्तन का कोई साक्ष्य प्राधिकारी की दृष्टि में नहीं आया है।

व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां एवं विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

88. सम्बद्ध वस्तुओं का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है और घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां विद्यमान नहीं हैं। भारतीय उत्पादक परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं और साथ ही सम्बद्ध

वस्तुओं की पहुँच कीमतों से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। उत्पाद का स्वरूप ऐसा है कि सम्बद्ध वस्तुओं की पहुँच कीमत से बाजार में इसकी कीमत आसानी से प्रभावित होती है। यदि आयातित उत्पाद सस्ता हो, तो इस पर निर्भरता बढ़ जाएगी।

प्रौद्योगिकी का विकास एवं निर्यात कार्य निष्पादन

89. यह नोट किया गया है कि इस उत्पाद की उत्पादन प्रौद्योगिकी में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है और भविष्य में भी परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। अतः प्रौद्योगिकी का विकास क्षति का सम्भावित कारण प्रतीत नहीं होता। यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने सम्बद्ध वस्तुओं की अल्प मात्रा का ही निर्यात किया है, जिससे कम्पनी के प्रचालन पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ता। अतः घरेलू उद्योग द्वारा की गई समस्त बिक्री की तुलना में घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन उल्लेखनीय नहीं है। किसी भी स्थिति में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट नहीं आई है और न ही प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई वर्तमान क्षति के निर्धारण में निर्यात की मात्रा व मूल्य पर विचार किया है।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

90. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि देखी गई है। उत्पादकता में सम्भावित गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण प्रतीत नहीं होती।

91. अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है। तथापि पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाने की स्थिति में पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति की सम्भावना है।

कारणात्मक संबंध को स्थापित करने वाले कारक

यद्यपि उपर्युक्त मानदण्डों से यह स्थापित होता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है, तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मानदण्डों से यह स्थापित होता है कि पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाने की स्थिति में पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति सम्भावित है :-

(क) पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में सम्बद्ध देशों से आयातों के कारण उल्लेखनीय कीमत कटौती होगी।

(ख) पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में उल्लेखनीय कीमत कटौती के परिणामस्वरूप उपभोक्ता आयातित सामग्री का अधिकाधिक उपयोग करेंगे, क्योंकि इस उत्पाद की कीमत अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक है।

(ग) यद्यपि जांच अवधि के दौरान आयातों की मात्रा उल्लेखनीय नहीं थी, तथापि यह पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाने की स्थिति में इसके सम्भावित प्रभाव को स्थापित करने की दृष्टि से उल्लेखनीय है। यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाने पर घरेलू उद्योग के कीमतों में उल्लेखनीय कमी करने पर बाध्य होने की सम्भावना है।

(घ) पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाने और तत्पश्चात् विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग कीमतों में कमी करने अथवा बिक्री की मात्रा में कमी करने पर बाध्य होगा। यदि घरेलू उद्योग कीमतें घटाने पर बाध्य हो जाता है, तो इसकी लाभप्रदता, नकद प्रवाह तथा निवेश से आय पर प्रतिकूल तथा वास्तविक दुष्प्रभाव पड़ेगा। यदि उपभोक्ता आयातित सामग्री का अधिकाधिक उपयोग करने लगते हैं, तो घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा में गिरावट आएगी। इस प्रकार दोनों स्थितियों में घरेलू उद्योग को क्षति सम्भावित है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के पिछले दुष्प्रभाव से उबर गया है। यदि प्रचालित पाटनरोधी शुल्क इस चरण में समाप्त कर दिए जाएं तो इस प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी। पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग पाटित आयातों से होने वाली क्षति का सामना करने के लिए पुनः बाध्य हो जाएगा। ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को पुनः क्षति होने की सम्भावना है।

क्षति जारी रहने अथवा निरंतर होने की सम्भावना

92. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि निर्णायक समीक्षा के अन्तर्गत यह जांच करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाने पर घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा निरंतर होते रहने की संभावना है; अतः जोखिम विश्लेषण हेतु सूचीबद्ध कारकों के आधार पर की गई जाँच त्रुटिपूर्ण होगी। अतः प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए ऐसे सभी कारकों की जांच यह ज्ञात करने के लिए की गई कि क्या पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाने की स्थिति में क्षति जारी रहने की सम्भावना है। प्राधिकारी ने ज्ञात किया है कि पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाने की स्थिति में पाटित कीमतों पर सम्बद्ध वस्तुओं का प्रवेश भारतीय बाजार में जारी है अथवा सम्बद्ध देशों से पाटित कीमतों पर इनका निर्यात सम्भावित है। यह जांच करना जरूरी है कि यदि शुल्क हटा लिया जाए तो क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति निरंतर होती रहेगी। यह पहले ही सिद्ध किया जा चुका है कि पाटनरोधी शुल्क के बिना सम्बद्ध देशों से आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग हेतु निर्धारित क्षति रहित कीमत से कम था।

93. लगातार हुई क्षति की जांच के अलावा प्राधिकारी द्वारा जांच के दौरान विभिन्न सम्बद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं साक्ष्य के आधार पर घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा निरंतर होते रहने की सम्भावना की भी जांच की गई। प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अनुबंध-II (vii) के अनुसार, जो निम्नानुसार है, वास्तविक क्षति खतरे के संबंध में उल्लिखित मानदण्डों पर विचार करते हुए क्षति जारी रहने अथवा निरंतर होते रहने की सम्भावना की जांच की गई :-

* वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों के आधार पर किया जाएगा और न की केवल आरोप, कल्पना अथवा परोक्ष संभावना के आधार पर। परिस्थितियों में होने परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऐसी किसी स्थिति का स्पष्ट तौर पर अनुमान लगाया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति आसन्नवर्ती होनी चाहिए जिसमें पाटन से क्षति पहुँचेगी। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में आकलन करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाएगा :-

(क) भारत में पाटित आयातों की अत्यधिक वृद्धि पर जो पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयातों की संभावना को दर्शाती हो।

(ख) निर्यातक के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य पर्याप्त क्षमता या असान्त्वर्ती वृद्धि जो किन्हीं अतिरिक्त निर्यातों को समाविष्ट कर लेने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना को प्रदर्शित करती हो ।

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर किए जा रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर पर्याप्त न्यूनकारी या ह्रासकारी प्रभाव पड़ेगा तथा इससे आगे और आयातों की मांग में वृद्धि की संभावना बनेगी; और

(घ) वस्तुओं की सामान सूची की जांच की जा रही है ।

94. पिछली जांच को छोड़कर सम्बद्ध देशों के किसी भी निर्यातक/उत्पादक अथवा किसी भी भारतीय आयातक/उपभोक्ता ने इस समीक्षा जांच का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है । घरेलू उद्योग ने अपनी सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यातक देशों की सम्बद्ध वस्तुओं के संबंध में क्षमता, उत्पादन तथा मांग की जानकारी उपलब्ध कराई है । यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान आयातों की मात्रा, सम्बद्ध तथा गैर सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं की आयात कीमतों का स्तर निर्यातक देशों के पास बेशी/मुक्त रूप से उपलब्ध निपटान क्षमता जैसे कारक यह दर्शाते हैं कि पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाने की स्थिति में सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाएगी । ऐसी स्थिति में जब पाटनरोधी शुल्क लागत रहने के बावजूद वस्तुओं का भारत को निर्यात किया गया हो, तो पाटित आयातों की मात्रा में और भी अधिक वृद्धि सम्भावित है, यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिया जाए ।

95. इस समय लागू उपाय समाप्त करने के सम्भावित प्रभाव का आकलन करने के उद्देश्य से यह नोट किया गया कि सम्बद्ध देशों द्वारा अपने उत्पादन तथा निर्यात की मात्रा में वृद्धि कर लेने की सम्भावना के स्पष्ट संकेत प्राप्त हुए हैं । पाटन जांच के आधार पर यह सम्भावना है कि उपायों के अभाव में सम्बद्ध देशों के उत्पादकों पाटित कीमतों की नीति अपनाएंगे, जिससे घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होगी । सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार देखा गया है । पाटन तथा पाटन की सम्भावना के मद्देनजर इन देशों के निर्यातक उत्पादकों द्वारा कीमतें कम करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता । सम्बद्ध देशों के निर्यातकों के ऐसे व्यवहार और उनके द्वारा सम्बद्ध वस्तुओं के उल्लेखनीय मात्रा में निर्यात की क्षमता के कारण संवेदनशील वस्तु बाजार पर कीमतों में मंदी आने की सम्भावना है । इस प्रकार यह साक्ष्य दर्शाता है कि यदि उपाय वापस ले लिए जाएं, तो घरेलू उद्योग को क्षति निरंतर होते रहने की सम्भावना है ।

96. शुल्क वापस ले लिए जाने की स्थिति में सम्बद्ध देशों से आयातों की सम्भावित मात्रा तथा सम्भावित कीमतें, जिन पर ऐसे आयात किए जाएंगे; और ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर सम्भावित प्रभाव के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा विभिन्न प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं ।

97. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि सम्बद्ध देशों के निर्यातकों ने भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर सम्बद्ध वस्तु का निर्यात करना जारी रखा और सम्बद्ध देशों की बेशी क्षमताओं और उनके पास उपलब्ध बेशी माल के कारण सम्बद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा भारत में सम्बद्ध वस्तु का पाटन किए जाने की संभावना है । किसी भी हितबद्ध पक्षकार में वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया और इस प्रकार उन्होंने यह स्थापित करने में

सहायता की कि लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने से पाटन और परिणामी क्षति के पुनः प्रारंभ होने और जारी रहने की कोई संभावना नहीं है। घरेलू उद्योग ने बार-बार इस बात पर बल दिया कि घरेलू तथा आयातित सामग्री के बीच कीमत-अंतर इतना अधिक है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाए तो ये संबद्ध देश भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की अत्यधिक मात्रा का निर्यात नहीं करेंगे, वह भी जब विदेशी उत्पादकों के पास रूप से निपटान किए जाने योग्य क्षमताएं विद्यमान हैं।

98. वर्तमान एवं संभावित क्षमता, उत्पादन, बिक्री, आयात, निर्यात, घरेलू मांग, घरेलू बिक्रियों के संबंध में कीमत स्तर, तीसरे देशों तथा भारत को निर्यात, संबद्ध देशों से आयातों की संभावित कीमत के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई तथा प्राधिकारी के पास रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना/साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्कों एवं अभ्यावेदनों की जांच की गई थी। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को जारी रखना आवश्यक है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित मापदण्डों पर विचार किया :-

(i) मूल जांचों में निर्धारित पाटन मार्जिन;

(ii) वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन - इस प्रयोजनार्थ, जहाँ कहीं भी जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात हुए थे, उन पर विचार किया गया था और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया था। जहाँ जांच अवधि में भारत को कोई निर्यात नहीं किया गया था, वहाँ निर्दिष्ट प्राधिकारी ने तीसरे देशों को निर्यातों और निर्धारित सामान्य मूल्य तथा संस्तुत किए जा रहे बेंचमार्क पर विचार करते हुए पाटन की संभावना के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है।

(iii) विदेशी उत्पादकों द्वारा किए गए विस्तारों को ध्यान में रखते हुए, बेशी वर्तमान एवं संभावित क्षमताएं, भारत में विद्यमान कीमतें, निर्यात की पूर्व की वास्तविक और संभावित मात्रा;

(iv) पाटन की संभावना के संबंध में प्रकट किए गए अन्य तथ्य, जहाँ तक वे क्षति की संभावना के संगत हों।

99. इन कारकों की जांच किए जाने पर यह नोट किया गया था कि :-

(क) संबद्ध देशों के मामले में पाटन मार्जिन बहुत अधिक है;

(ख) संबद्ध देशों की निर्यात कीमत भारत में विद्यमान बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमत से बहुत कम है;

(ग) निर्यातकों द्वारा यह नहीं दर्शाया गया है कि पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना नहीं होगी और पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को लगातार जारी रखना आवश्यक है।

(घ) इस बात पर विचार करते हुए कि यूएई से वर्तमान निर्यात वचनबद्ध कीमतों पर हो रहे हैं, यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के साथ ही कीमत वचनबद्धता समाप्त हो जाए तो आयातों में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है;

(ड.) यूएई के उत्पादक ने अन्य देशों को बहुत अलग-अलग कीमतों पर संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। दो वर्ष से कम अवधि में बांग्लादेश को किए गए निर्यातों में 20 अम. डा. पीएमटी का बड़ा अंतर है (संबंधित उत्पादन लागत में नगण्य परिवर्तनों को देखते हुए बहुत अधिक)। इस प्रकार, प्रतीत होता है कि निर्यातक सामग्री को ऐसी कीमतों पर बेचने का इच्छुक है जिनमें बहुत अधिक अंतर है।

(च) विभिन्न देशों को यूएई के निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिनों में बहुत अधिक अंतर है जिससे पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने पर अत्यधिक पाटन की संभावना स्थापित होती है।

(छ) ऐसा प्रतीत होता है कि ईरानी उत्पादक स्थायी कीमत निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित अथवा अनुसमर्थित आधारभूत निर्यात कीमत पर उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं। इस प्रकार, निर्धारित कीमतें सामान्य मूल्य के आकलनों से बहुत कम हैं। यदि यह मान लिया जाए कि भारत को इन्हीं कीमतों पर निर्यात किए जाएंगे तो यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने पर पाटन पुनः प्रारंभ हो जाएगा।

(ज) ईरान तथा यूएई में सफेद सीमेंट की क्षमता, उत्पादन, माँग एवं खपत निम्नानुसार है :-

	ईरान	यूएई
क्षमता	929835	450000
उत्पादन	759251	311686
घरेलू माँग	420000	98030
निर्यात	339251	204048
अप्रयुक्त क्षमता	170584	138314

प्राधिकारी पाते हैं कि दोनों देशों में अत्यधिक अप्रयुक्त क्षमताएँ हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों देश कई देशों को निर्यात कर रहे हैं और इसलिए तीसरे देशों को होने वाले निर्यातों को भारत में किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(झ) यूएई तथा ईरान के पास बहुत अधिक मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताएँ हैं। न केवल उत्पादक के पास अत्यधिक अप्रयुक्त क्षमताएँ हैं बल्कि उत्पादक विभिन्न देशों को बहुत अधिक निर्यात भी कर रहा है। प्राधिकारी मानते हैं कि इन निर्यातों का गंतव्य उस कीमत पर निर्भर करेगा जो उत्पादक को प्राप्त होगी।

(ञ) यह नोट किया गया है कि सफेद सीमेंट के निर्यातों के अलावा इन देशों से क्लिंकर का बहुत अधिक निर्यात हुआ है। हालांकि न तो क्लिंकर को शामिल करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे में विस्तार करना उचित है और न ही क्लिंकर के आयातों पर विचाराधीन उत्पादों के आयात के रूप में विचार करना उचित होगा, तथापि यह स्पष्ट है कि निर्यातक क्लिंकर के बजाय सफेद सीमेंट के निर्यात को वरीयता देंगे। अतः, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की संभावना के निर्धारण के लिए निर्यात की मात्रा और जिस कीमत पर ये निर्यात किए जा रहे हैं, भी प्रासंगिक हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्लिंकर के निर्यातों की मात्रा बहुत अधिक है। जिस कीमत पर क्लिंकर का निर्यात किया गया है और क्लिंकर के बाद के मूल्यवर्धन पर विचार करने पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में निर्यातकों द्वारा क्लिंकर के बजाय सफेद सीमेंट का पाटित कीमतों पर निर्यात किए जाने की संभावना है।

(ट) संबद्ध देशों से कई देशों को किए गए निर्यात न केवल सामान्य मूल्य से बल्कि भारत में विद्यमान बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमत से भी बहुत कम कीमत पर हैं।

प्राधिकारी ने पाया है कि दोनों देशों के पास बहुत अधिक अप्रयुक्त क्षमता है। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों द्वारा कई देशों को निर्यात किया जा रहा है और इसलिए तीसरे देशों को किए जा रहे निर्यातों को भारत में भेजे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

	यूएई	ईरान
क्षमता	450000	930000
उत्पादन	311686	759251
क्षमता उपयोग	69.26	81.64
अप्रयुक्त क्षमता	138314	170749
आयात	0	0
कुल उपलब्धता	311686	759251
माँग	98030	420000
बेशी उपलब्धता	213656	339251
निर्यात	204048	246809
निवल बेशी उपलब्धता	9608	92442
निवल बेशी क्षमता	211970	263191

100. चूंकि संबद्ध देशों में बेशी क्षमता है, अतः यह नोट किया गया है कि भारतीय बाजारों में संबद्ध देशों से निर्यात किए जाने की संभावना है। रिकॉर्ड में उपलब्ध क्षमता, उत्पादन, बिक्री तथा माँग संबंधी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की परिणति अत्यधिक पाटन और अनुवर्ती क्षति के रूप में होगी और इसी कारण पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को जारी रखना आवश्यक है।

101. यह नोट किया गया है कि निर्यातकों ने रिकॉर्ड किए गए किसी भी ऐसे संतोषजनक साक्ष्य, कि उपायों को वापसी लेने के मामले में क्षति की पुनरावृत्ति नहीं होगी, के साथ सहयोग एवं भागीदारी नहीं की है। रिकॉर्ड किए गए क्षमता, उत्पादन, बिक्री एवं माँग के संबंध में साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क की वापसी से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहेगी।

रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य और हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी शुल्क के प्रतिसंहरण से संबद्ध देशों से पाटन की पुनरावृत्ति होगी।

102. उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी मानते हैं कि यदि शुल्कों का प्रतिसंहरण किया जाता है तो पाटन और क्षति जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

ज. क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन की गणना

103. अपने बाद के प्रकटन अनुरोधों में घरेलू उद्योग ने कई मुद्दों को उठाया है जो घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की गणना और क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु उत्तराई कीमत के साथ इसकी तुलना के संबंध में हैं। उठाए गए मुद्दों पर प्राधिकरण द्वारा जांच की गई है और संबद्ध वस्तु के लिए क्षति रहित कीमत की गणना घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों और अपनी उत्पादन लागत के संबंध में प्रदान की गई सूचना का विस्तृत विश्लेषण एवं उसकी जांच करने के पश्चात् की गई है। प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के लिए (****/प्रति एम.टी) भारित औसत क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया गया है।

झ. अंतिम जांच परिणाम

104. हितबद्ध पक्षों द्वारा दी गई दलीलों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए तथा हितबद्ध पक्षों के अनुरोध के जरीए प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों अथवा उपर्युक्त जांच परिणामों में अन्यथा दर्ज रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान एवं संभावित पाटन एवं क्षति के उपर्युक्त विश्लेषण तथा पाटन एवं क्षति जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :-

- (i) संबद्ध वस्तुएं भारतीय बाजार में पाटित, कीमतों पर प्रवेश कर रही है तथा संबद्ध देश से पाटन मार्जिन काफी अधिक और न्यूनतम सीमा से ज्यादा है। यदि वर्तमान उपाय वापस ले लिया जाता है तो संबद्ध वस्तु के भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश किए जाने की संभावना है।
- (ii) यद्यपि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान अपने निष्पादन में सुधार किया है और क्षति नहीं उठाई है तथापि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होगी।

सिफारिशें

105. इस आशय का निष्कर्ष निकालने के बाद कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है और यदि शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, प्राधिकारी का मत यह है कि संबद्ध देशों से आयात के विरुद्ध इस उपाय को जारी रखना आवश्यक है।

106 प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने को जारी रखना आवश्यक समझते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। प्राधिकारी पाटन मार्जिन के बराबर या उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है तो इससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी।

107. तदनुसार, प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 25 के तहत सूची 1 की सीमाशुल्क शीर्ष 2523.21 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तु के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा नीचे निर्धारित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाते हैं। पाटनरोधी शुल्क सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय -25 के अंतर्गत नीचे उल्लिखित संबद्ध क्षेत्रों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 9 में उल्लिखित राशि होगी :-

क्र. सं.	उप-शीर्ष	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि (अम.डा.)	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2523.21	व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट	कोई	यूएई	ईरान से इतर कोई देश	कोई	कोई	32	प्रति एमटी	अम.डा.
2	2523.21	व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट	कोई	यूएई से इतर कोई देश	यूएई	कोई	कोई	32	प्रति एमटी	अम.डा.

3	2523.21	व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट	कोई	ईरान	यूएई से इतर कोई देश	कोई	कोई	38	प्रति मी.टन	अम.डा.
4	2523.21	व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट	कोई	यूएई से इतर कोई देश	ईरान	कोई	कोई	38	प्रति मी.टन	अम.डा.

108. इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुँच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार शुल्क शामिल होंगे।

109 प्राधिकारी उक्त अधिनियम के संगत उपबंधों और समय-समय पर इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार समय-समय पर इसमें यथा अनुशंसित निश्चयात्मक उपायों को जारी रखना, उनमें संशोधन करने या उनकी समाप्ति की आवश्यकता की समीक्षा कर सकता है। प्राधिकारी द्वारा ऐसी समीक्षा के लिए किसी अनुरोध पर तब तक कोई विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई इच्छुक पक्षकार इसे इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय-समय के भीतर प्रस्तुत नहीं करता है।

110. इस आदेश के विरुद्ध अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (यथा-संशोधित) के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद तथा सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

क्रिस्टी फेर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2007

FINAL FINDINGS

Subject : Anti-dumping Sunset Review Investigation concerning imports of White Cement originating in or exported from UAE and Iran.

No. 15/6/2005 DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules);

A. BACKGROUND

- 2 WHEREAS, having regard to above Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) initiated an antidumping investigation on 6.12.2000 into alleged dumping of White Cement originating in or exported from UAE and Iran and provisional antidumping duty was imposed on imports of White Cement from UAE and Iran vide customs notification no. 64/2001-CUS dated 14.06.2001 on the basis of the preliminary findings of the Authority dated 22.02.2001. The final findings were notified vide notification dated 30.08.2001 and the Department of Revenue imposed definitive anti dumping duties on the subject goods from subject countries vide notification no. 99/2001-CUS dated 03.10.2001.

- 3 On the basis of a duly substantiated application filed by the Domestic Industry in terms of Section 9A(5) of the said Act requesting for review, continuation and enhancement of anti dumping duty in force for a further period of five years, the Designated Authority initiated a sunset review investigations vide notification no. 15/6/2005-DGAD dated 28th Feb 2006, to examine whether the expiry of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and/or injury. Investigation was carried out for the period starting from 1st October 2004 to 30th September 2005 (POI) (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2002-03, 2003-04, 2004-05 and POI.

B PROCEDURE

- 4 The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
- i) The Designated Authority under the above Rules, received an application filed by M/s. J K White Cement Works (Unit of J K Cement Limited) Gotan – Nagour – Rajasthan, supported by M/s Grasim Industries Ltd. (White Cement Division), Kharia Khangar - Jodhpur, Rajasthan requesting initiation of sunset review investigation for review, continuation and enhancement of anti dumping duties concerning imports of White Portland Cement (hereinafter referred as white cement or subject goods) originating in or exported from United Arab Emirates (UAE) and Iran (hereinafter referred to as subject countries).
 - ii) The information provided by the applicant showed sufficient prima facie justification that there was a need for sunset review of anti dumping duties earlier imposed. On being satisfied, the Authority issued a public notice dated 28th Feb, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping sunset review investigation concerning imports of the subject goods classified under Chapter 25 of the Custom Tariff Act (Section V of the Act, which pertains to Mineral Products) under the sub-heading 2523.21 originating in or exported from UAE and Iran.
 - iii) The Authority forwarded a copy of the public notice to the known producers and/or exporters in the subject countries and provided them opportunity to provide relevant information and make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rule 6(2)
 - iv) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and/or consumers of subject goods in India and advised them to provide relevant information and make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(2).
 - v) Requests were made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) and Director General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata to arrange details of imports of subject goods in India for the period of investigation and preceding three years. Specific request was also made to Indian Embassy in Iran and UAE to provide relevant information with regard to exports of the subject goods from these countries. Specific request was also made to Commissioner of Customs ICD – New Delhi,

Cochin, Navi Mumbai and Chennai to provide the import data, as according to domestic industry, imports are taking place at these ports. Information was however, received only from ICD Cochin.

vi) The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known producers and/or exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential application was also made available for other interested parties, on request.

vii) The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the government of subject countries, including following known exporters/producers in accordance with the Rule 6(4) :-

M/s. Saveh White Cement C., Tehran, Iran.
 M/s. Urmia White Cement, Tehran, Iran.
 M/s. Shomal White Cement Company, Tehran, Iran.
 M/s. Benvid White Cement, Tehran, Iran.
 M/s. Neyriz White Cement, Tehran, Iran.
 M/s. Ras Al Khaimah Co. UAE.

Mr. George Poonthottan – Advocate for RAK UAE requested for extension of time for filing response upto 31 December 2006, which was granted by the Designated Authority upto 15th December 2006. However none of the exporters/producers from the subject countries filed response to the questionnaire.

viii) Questionnaire was sent to the following known importers or users of the product under consideration for providing necessary information in accordance with Rule 6(4). The Authority provided opportunity to the industrial users of the product under consideration, to furnish information considered relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality:

1. Gardewel Industries, Pune
2. Sonalac Paints & Coatings Ltd., Kathua
3. Golden Paints & Chemicals, Amritsar.
4. Super Chem Paint Pvt. Ltd., Jalandhar
5. Marvel Paint Co. Ludhiana.
6. Crete Industries, Solan
7. Meena Industries, Shivakasi
8. Rainbow Colours India, Kamal
9. Oriental Colour & Paint P. Ltd.
10. Aquolac Paints, New Delhi
11. Pegasus Indian Textilaties, Vasai
12. Acro Paints Ltd. Bhiwadi(Raj)
13. Poona paints & Vamishes Pvt. Ltd.
14. Evershine Paints & Chemical Ind. New Delhi
15. Power Paint(I) Ltd. Noida
16. Super Aquacem (India) Pvt. Ltd. Gurgaon
17. Rainbow Concretes (P) Ltd. Panchkula
18. Brite Paint & Chemical Co. Sahibabad
19. Snowcem India Ltd. Gotan

20. Nitco Coating Industries, Kanpur
21. Super Coats Paints (P) Ltd., Bangalore
22. U.P.R.N.N.(Allahabad Unit), Itawa
23. Supermix Const. Chem (I) P. Ltd., Mumbai
24. Jay Industries, Ahmedabad
25. Tista Decocem Pvt. Ltd. Siliguri
26. Pravin Tiles Co. Morvi(Gujrat)
27. Triveni Colour Industry, Valsad
28. Sun Coats, Rajkot
29. U.K. paints India Pvt. Ltd. Greater Noida
30. Choice Mosaic Tiles, Silvassa
31. Unistone Products (India) Pvt. Ltd. New Delhi
32. Santosh Tiles, Silvassa
33. Valli Paints, Chennai
34. Ceracem Coating India Pvt. Ltd. Thane
35. Vigneshwara Industries, Shivakasi
36. Gem Chemicals, Aurangabad
37. S.K. Tiles, Raipur
38. Laticrete India Pvt. Ltd. Hyderabad
39. Konark Flooring, Hubli
40. Anugraha Tiles and Marbles, Bangalore
41. Rainbow Colour Chems, Tirunelveli
42. Aries Industries, Pondicherry
43. Gemini Paints, Chennai
44. Madras Cement Ltd. Kanchipuram
45. Comtrust Super Designer Tiles (P) Ltd. Palkkad
46. Crimson Paints Pvt. Ltd. Kolkata
47. Grindchem Unit II, Jamshedpur
48. Unichem Paints (I) Pvt. Ltd. Guwahati
49. Gengara Marketing Agency, Kerala

Following parties have filed their submissions/response/ information to the Designated Authority.

- (1) Super Aquacem (India) Pvt. Limited.
- (2) Indian Small Scale Paint Association.
- (3) Anugraha Tiles & Marbles, Bangalore
- (4) Mr. H Bandur - Bangalore

- ix) The Authority held a public hearing on 7th November 2006 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally, which was attended by J. K. Cements Limited, Grasim Industries Limited, TPM Consultants (consultants for J K Cements and Grasim Industries), and representative of Government of UAE. Advocate of exporter from UAE also attended the hearing. The parties attending the public hearing were advised to file written submissions of the information presented orally. The interested parties were allowed to present rebuttal arguments on the views/information presented orally by other interested parties. Designated

Authority has considered these written submissions received from interested parties.

- x) Arguments raised and information/evidence provided by various interested parties during the course of the investigation, to that extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, are appropriately considered by the Authority in these findings.
- xi) The Authority during the course of investigation satisfied itself as to the accuracy of the information supplied upon which these findings are based. For that purpose, the Authority conducted on-the-spot verification of the domestic industry to the extent considered relevant and necessary. Additional/ supplementary details regarding injury were sought from the domestic industry, which were also received.
- xii) In accordance with Rule 16 of the Rules *supra*, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same are considered in Final Findings.
- xiii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties through a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).
- xiv) Cost investigations were conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicant so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xv) ***** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules on merits.
- xvi) Investigation was carried out for the period starting from 1st October 2004 to 30th September 2005 (12 months and has been referred to as the period of investigation (POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2002-03, 2003-04, 2004-05 and POI.
- xvii) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded findings on the basis of the facts available.
- xviii) Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted and

such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:

C.1 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

5 Domestic industry has made following submissions:-

- (i) The present petition is filed requesting the Hon'ble Designated Authority to initiate a sunset review with regard to the anti dumping duty in force on the imports of White cement (in finished and semi finished condition) from United Arab Emirates (hereinafter referred as UAE) and Iran.
- (ii) The petitioner is filing this petition for the review, enhancement and continuance of anti dumping duty in force against dumping of White Cement in the Indian market by the producers and/or exporters of United Arab Emirates (UAE) and Iran.
- (iii) Being a review investigation, product under consideration in the present petition is the same as has been in the original investigation.
- (iv) The product under consideration in the present petition is White Portland Cement, which is generally referred to as White Cement in this petition and market parlance. The complete description of the product including nomenclature, formula, description, grades, assay, uses, packing, transport, classification, handling and storage precautions etc. in respect of the product under consideration being imported from the subject countries is already examined by the Designated Authority in the original investigations and the relevant information is on record of the Designated Authority.
- (v) White Cement is construction material and it is primarily used for non-structural purposes. It is used for architectural purposes, flooring, manufacturing of flooring tiles, cement based exterior paints and cement wash (white wash). White Cement has low content of soluble alkalies and does not cause stain.
- (vi) Exporter from M/s. RAK is exporting substantial volumes of Clinker in addition to White Cement in Indian market. Clinker is nothing but raw white cement. The only additional production process required to obtain white cement from clinker is incremental and grinding and mixing of gypsum.
- (vii) Clinker has no use other than further processing into white cement. Imports of clinkers are nothing but imports of raw or unfinished or semi-finished white cement. In view of the above, petitioner submitted that clinker should be included within the scope of the product under consideration.
- (viii) Producers from subject countries in general and Iran in particular are exporting not only white cement, but also semi finished white cement

(clinker) to a number of countries. Following information has been provided to the Authority.

(ix) **Exports from Iran**

Volume in MT

White Cement	2000-01	2001-02	2002-03
Urmia White	0	15462	18822
Shomal White	4932	1884	492
Saveh White	55809	80513	64359
Neyriz White	37682	29293	11844
Total	98423	127152	95517

Clinker	2000-01	2001-02	2002-03
Urmia White	0	7148	9255
Shomal	0	0	0
Saveh White	70855	43064	102935
Neyriz White	53333	54020	39102
Total	124188	104232	151292

Clinker and Cement total			
Urmia White	0	22610	28077
Shomal	4932	1884	492
Saveh White	126664	123577	167294
Neyriz White	91015	83313	50946
Total	222611	231384	246809

- (x) The Iranian producers are exporting white cement and clinker i.e. semi finished white cement regularly to several countries. In fact exports of clinker are higher than white cement.
- (xi) A number of arguments were advanced by the petitioner requesting that the product scope needs to be reconsidered and re-clarified/modified in this case and clinker need be included in the scope of the product under consideration.
- (xii) Though White Cement has been categorized under dedicated customs sub-heading, it is possible that imports have been reported under other custom heads.
- (xiii) Petitioner submits that these producers would resort to dumping, should the present Anti Dumping Duties be revoked. The petitioner is aware, based on their market information, that producers/ exporters in subject country have been exporting significant volumes of the product under consideration to a number of other countries at dumped price as is evident from the table below.

S	In case of Iran	Price US\$/MT	In case of UAE	Price US\$/MT
N				
1	Uzbekistan	75.62	Bangladesh (Evidence 1)	80.00
2	UAE	77.22	Bangladesh (Evidence 2)	66.00

3	Turkmenistan	76.56	Hong Kong	99.40
4	Tajikisthan	74.62	Germany	89.38
5	Sri Lanka	80.00	Eritrea	103.99
6	South Africa	80.00	Tanzania	101.75
7	KSA	70.39	Oman	85.70
8	Russia	75.82	Iraq	70.16
9	Qatar	62.93	Netherlands	90.31
10	Phillipines	70.00	Pakistan	97.07
11	Kyrgystan	75.52		
12	Kuwait	75.06		
13	Kazakhstan	75.28		
14	Iraq	74.95		
15	Georgia	75.75		
16	Denmark	76.41		
17	Agerrbazan	76.53		
18	Armenia	76.13		
19	Afganistan	75.18		

- (xiv) The goods produced by the domestic industry are like article within the meaning of anti dumping Rules.

C.2 VIEWS OF THE IMPORTERS, CONSUMERS, EXPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

- 6 None of the importers, consumers, exporters and other interested parties filed any comment or submissions with regard to product under consideration, like articles, scope of the present investigations and scope of the domestic industry.

C.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 7 The product under consideration in the present investigation is White Portland Cement commonly known as White Cement (referred to as White Cement in the present investigation) originating in or exported from subject countries. The product under consideration is the same as considered in the original investigation. White Cement is a construction material, used for non-structural purposes such as flooring of tiles, cement based exteriors, paints and cement varnish etc.
- 8 White cement falls under Chapter 25 of the Custom Tariff Act under the sub-heading 2523.21. Classification of chapter-25 concerning this product is given below.

Chapter/ Subheading	Description
Chapter 25	Salt; sulphur; earth and stone; plastering materials, lime and cement

25.23	Portland cement, alumnus cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers.
2523.10	Cement Clinkers
2523.1000	Cement Clinkers
2523.21	White Cement, whether or not artificially Coloured
2523.2100	White Cement, whether or not artificially Coloured

- 9 The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of investigation.
- 10 With regard to inclusion of cement clinker within the scope of the investigation, Authority notes that present investigation is a sunset review investigation. Scope of the product under consideration should therefore be the same as has been in the original investigation.
- 11 In the initiation notification, the scope of the product under consideration was specified as follows –

The product under consideration is White Portland Cement commonly known as White Cement. White Cement is construction material and it is primarily used for non-structural purposes. It is used for architectural purposes, flooring, manufacturing of flooring tiles, cement based exterior paints and cement wash (white wash). White Cement has low content of soluble alkalies and does not cause stain. White Cement is classified in Chapter 25 of the Custom Tariff Act (Section V of the Act, which pertains to Mineral Products) under the sub-heading 2523.21. The Customs and ITC HS classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

- 12 In comments to disclosure statement, the domestic industry has reiterated that exports of cement clinker from the subject countries are significant in volumes. While reiterating their request for inclusion of cement clinker, the domestic industry has reiterated that the price at which cement clinker has been exported should also be used as the basis for determination of likelihood of recurrence of dumping of white cement from the subject countries. Having regard to the evidence of record and initiation notification, the Authority considers it appropriate to restrict the scope of the product under consideration to the same as was kept before. The Authority therefore defines the product under consideration as White Portland Cement.
- 13 In order to determine whether goods produced by the domestic industry can be considered like article to the goods produced and/or exported from the subject countries, Designated Authority notes that the issue has been examined by the Designated Authority in earlier investigation, and no submissions received by the Designated Authority, opposing previous determination of the Authority. Authority confirms that the material

produced by the domestic industry is like article to the goods imported or produced in subject countries within the meaning of the Rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY

D.1 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

14 Domestic industry made following submissions regarding domestic industry.

- (i) The present petition was filed by J. K. White Cement Works (which is a unit of J. K. Cement Limited) and supported by Grasim Industries Limited – White Cement Division. There are three companies in India who created capacity for production of white cement.
- (ii) Production of petitioner constitutes a major proportion in Indian Production and therefore petitioner should be treated as “domestic industry” within the meaning of the Rules. In any case, post initiation, Grasim Industries filed complete relevant information. Production of these two companies command more than 95 % of Indian Production. The two companies therefore should now be treated as domestic industry.

D.2 VIEWS OF THE EXPORTER, IMPORTERS, CONSUMERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

15 None of the other interested parties filed any submissions in this regard.

D.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

16 As per Rule 2(b) of the AD Rules, “domestic industry means the domestic producers as a whole engaged in manufacture of like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers may be deemed not to form part of domestic industry.”

17 Production of Indian industry in period of investigation is as under:

Producer	Production in MT
Grasim Industries Limited	339171
J K White Cement Works	223714
The Travancore Cements Limited	21219
Total Indian Production	584104

18 Production of the petitioner company constituted a major proportion in the Indian production. Further, the petition was supported by M/s. Grasim Industries Ltd. and the Travancore Cements Limited. Therefore, the petition

is considered to have been made by the domestic industry within the meaning of Anti Dumping Rules.

19 Upon initiation, the Authority directed other Indian Producers, M/s. Grasim Industries Limited and the Travancore Cements Limited to provide relevant information. M/s. Grasim Industries Limited and the Travancore Cements Limited provided information with regard to determination of injury and offered itself for verification. The information provided by the companies has been verified to the extent considered necessary.

20 Based on the Information available on records of the Designated Authority, petitioners and supporters account for 100% Indian production and constitute domestic industry within the meaning of the Rules.

E. OTHER ISSUES

E.1 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

21 The Domestic industry has submitted as under:-

- (i) The petition was complete in all respect and adequate and accurate evidence was provided to the Authority prior to initiation, which formed the basis for initiation of sunset review investigation.
- (ii) M/s. Ras Al Khaimah participated in the earlier investigation and had given a price undertaking, which has been violated by the company on a number of accounts. Therefore, the Authority should now revoke the undertaking and impose definitive anti dumping duties instead.
- (iii) No response from foreign producers confirms the claims of the domestic industry. These parties have not responded only because the data would have otherwise shown that the product is likely to be dumped in significant volumes in the event of revocation of anti dumping duties.
- (iv) The representative of exporter from UAE attended the hearing without providing any information. Nor any submissions have been filed thereafter. Exporter should not be allowed to make any argument and submissions in the present investigation, considering that there is no timely submission by the exporter.
- (v) Domestic industry submits that export volume reported by the exporting country is significantly higher than the import volume reported by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.
- (vi) Domestic industry provided evidence to the Designated Authority showing imports of White Cement from UAE, which has not been reported in DGCI&S data.

- (vii) The UAE producer continued to export subject goods to India at dumped price throughout the period, which went unnoticed due to the fact that the same are not getting reported in DGCIS.
- (viii) M/s. The Travancore Cements Limited has supported the petition and claimed that the anti dumping duty on white cement should be continued. They are the oldest producer of white cement in India. The company is a Kerala Government undertaking and has been a profitable company for the several years till 2000 before dumping from the subject countries. The company is using old wet process. If imports of white cement are permitted, the company will not be able to sell its material and the company will not be able to achieve even present volumes.

E.2 VIEWS OF THE EXPORTER, IMPORTERS, CONSUMERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

- 22 Exporters, importers, consumers and other interested parties submitted as under:
- (i) Super Aquacem India Pvt. Limited filed its questionnaire response. No other submissions/arguments were made by the company.
 - (ii) Indian Small Scale Paint Association submitted that the association represents the majority of paint manufacturers in India and the membership is well over 1600. White cement is an integral part of some coatings made by its members. Continuation of anti dumping duty on white cement is harmful to the interest of small scale manufacturers. By retention of anti dumping duty government will only protect the interests of large scale manufacturers while hurting the interest of small scale paint units. Extension of anti dumping duty will only protect local manufacturers. In case there are any aggrieved local manufacturers of white cement who feel that such anti dumping duty is required to be continued, the association requests the Authority to refer the matter to BICP to examine their manufacturing costs vs. their MRP.
 - (iii) Anugraha Tiles & Marbles, Bangalore requested for a copy of the questionnaire, which was sent. The company however, did not file any Information/ submissions.
 - (iv) Advocate for RAK filed a letter and claimed that imports volume from UAE constitute less than 1% compared to sales of the domestic industry and domestic industry is also exporting white cement at a price less than US \$ 100 per MT.
 - (v) Mr. H Bandur – Bangalore has filed a letter and made claims regarding landed price of imports. The company also claimed that domestic producers are misleading the Authority. However, same was not supported with any evidence

E.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

- 23 Designated Authority notes submissions made by various interested parties. As regard the submissions made by Indian Small Scale Paint Association, the Authority notes that none of the members of this association responded to the Authority with relevant information, nor the association established how imposition or continuation of anti dumping duties is acting against their interests. The Authority also notes the present investigations are based on verified cost structures of Indian Producers. It would therefore be unnecessary to get cost structures verified through BICP. The argument that imports volume from UAE constitute less than 1% compared to sales of the domestic industry and domestic industry is also exporting white cement at a price less than US \$ 100 per MT. is not relevant as the investigation is to examine whether the expiry of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and/or injury. Regarding violation, if any, of price undertaking given earlier by RAK the Authority notes that Indian producers have already filed a separate petition which shall be decided as per Rules.

Neither the domestic industry has argued continued injury, nor the Designated Authority has found that the domestic industry has suffered continued injury. As noted in these findings, the evidence on record establishes that revocation of the present anti dumping duties would lead to significant price difference between the domestic and imported product and is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry. The Authority also notes that none of the producers in the subject countries have cooperated with the Authority. While evidence on record suggests that revocation of anti dumping duty would lead to recurrence of dumping and injury, these foreign producers or the importers or consumers in India have not been able to establish that no injury would be caused to the Indian Producers as a result of revocation of anti dumping duties.

CALCULATION OF DUMPING AND DUMPING MARGIN**F. DUMPING MARGIN****F.1. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY**

- 24 Domestic industry submitted as under:
- (i) The product continues to be exported at dumped prices. Even though the volumes have declined, yet, whatever exports have been made, the same are at significantly dumped prices.
 - (ii) The evidence collected on the basis of the customs data of the exporting country UAE show that the actual volume of imports is higher than what is reflected in the Indian official statistics, as shown in the table below –

Particulars	As per DGCIS	As per Actual Evidence	As per Country Data	Exporting
Period ---->	POI	Within POI	2004	2005
Volume	0	280	2606	4014
Price US \$ MT	0	100	67	90
Ex-factory Export Price	0	73.50	56.02	63.29
Normal Value	0	108.86	108.86	108.86
Dumping Margin	0	35.36	52.84	45.57
Dumping Margin %	0	48.11	94.31	71.99

- (iii) Considering the estimates of normal value and the above export price, it would be seen that the dumping margin is quite significant. Given that the current exports are at dumped prices, it is evident that dumping would at best intensify with revocation of anti dumping duties.
- (iv) While considering the export price from UAE, it should be noted that this is the price at which exporter has exported the material under price undertaking agreement. Therefore, this price would not establish full extent to which these producers can dump the product. Should the price at which exports are being made to third countries be examined, it would be seen that the extent of dumping is quite significant. Exports made by the sole UAE producer to Bangladesh, Indonesia, Hongkong, Germany, Kenya, China, Belgium, Eritrea, USA, Tanzania, Sri Lanka, South Africa, Oman, Iraq, Netherlands, Pakistan as shown below reflects the extent to which the exporter would resort to dumping. There is significant export of subject product from UAE and Iran to world countries at prices significantly below associated normal value.

SN	Country	Volume	Price	Ex-fact.	Dumping	Dumping
	<u>Iran</u>	Mt	US\$/MT	Price	Margin	Margin %
1	Uzbekistan	34	75.62	49.99	58.87	67.12
2	UAE	10,898	77.22	51.58	57.28	63.13
3	Turkmenistan	282	76.56	50.93	57.93	64.75
4	Tajikistan	628	74.62	49.00	59.87	69.71
5	Sri Lanka	28	80.00	54.35	54.51	56.64
6	South Africa	26	80.00	54.35	54.51	56.64
7	KSA	43,686	70.39	44.79	64.07	81.62
8	Russia	1	75.82	50.19	58.67	66.61
9	Qatar	24,635	62.93	37.37	71.50	107.30
10	Phillipines	20	70.00	44.40	64.46	82.81
11	Kyrgystan	2	75.52	49.89	58.97	67.37
12	Kuwait	10,868	75.06	49.43	59.43	68.56
13	Kazakhstan	975	75.28	49.65	59.21	67.99
14	Iraq	90,423	74.95	49.33	59.54	68.84
15	Georgia	4	75.75	50.12	58.74	66.78
16	Denmark	1	76.41	50.78	58.08	65.12
17	Agerrbazan	1,008	76.53	50.90	57.96	64.82

18	Armenia	1,041	76.13	50.50	58.36	65.82
19	Afganistan	3,973	75.18	49.55	59.31	68.25

SN	Country	Volume	Price	Ex-fact.	Dumping	Dumping
	UAE	Kg	US\$/MT	Price	Margin	Margin %
1	Hongkong	3,923	99.40	88.80	20.06	22.59
2	Germany	635	89.38	78.83	30.03	38.09
3	Ethopia	26	20.95	10.74	98.12	913.41
4	Eritrea	862	103.99	93.37	15.49	16.59
5	USA	4,140	106.44	95.81	13.06	13.63
6	Tanzania	142	101.75	91.14	17.72	19.44
7	Sri Lanka	336	114.76	104.08	4.78	4.59
8	South Africa	1,539	113.91	103.24	5.62	5.44
9	Oman	352	85.70	75.17	33.69	44.82
10	Iraq	1,921	70.16	59.70	49.16	82.33
11	Netherlands	285	90.31	79.76	29.10	36.49
12	Pakistan	2,598	97.07	86.48	22.38	25.87

- (v) Imposition of the anti dumping duty has acted as a deterrent. Dumping would at best intensify with the revocation of the anti dumping duties.
- (vi) There is sufficient reason to believe that the exporter from UAE would shift back their exports to India at dumped prices should the present duties be revoked, considering the price prevailing in the Indian market, price at which goods have been exported to various countries and available capacities with the foreign producers. Comparison of current export prices with the prices prevailing in India would show that the prices in the Indian market are too lucrative to the foreign producers.
- (vii) Demand of White Cement in exporting countries are significantly lower than (1) capacity created and (2) present production levels.
- (viii) Even if it is assumed that there was no dumping of the subject goods in the period of review investigation, the same only establishes that the present measures have been able to prevent dumping and this at best establishes that there is a need for continuation of the present measures.
- (ix) The following data shows that dumping is likely to intensify from UAE in the event of revocation of anti dumping duties.

Particulars	Unit	Volume	Source
Capacity	MT	450000	Global White Cement Report
Production	MT	380000	Khaleej Times 2005 – 08.05.05
Demand	MT	120000	Global White Cement Report
Excess Production	MT	260000	Calculation
Capacity Utilization	%	84.44	Calculation

Unutilized Capacity	%	15.56	Calculation	
Unutilized Capacity	MT	70000	Calculation	
Excess Capacity	MT	330000	Calculation	
Future Expansion	MT	150000	Industry's Market Sources	
Potential excess capacity	MT	220000	Calculation	
Present exports	MT	140000	Calculation	
Potential excess capacity	MT	480000	Calculation	
Excess present capacity as % of demand	%	175%	Calculation	
Excess future capacity as % of demand	%	400%	Calculation	

- (x) With regard to Iran, the domestic industry provided following information and claimed existence of surplus capacities in Iran.

2005-06	Capacity	Production	Capacity Utilization
Urmia White	163,807	166346	101.55
Benvid White	163,809	130703	79.79
Shomal White	89,238	41665	46.69
Saveh White	327,618	279753	85.39
Niyriz White	185,364	140784	75.95
Total	929,835	759,251	81.65%
Unutilized Capacity	170,584		
2004-05			
Urmia White	163,794	181271	110.67
Benvid White	163,779	120427	73.53
Shomal White	89,235	79544	89.14
Saveh White	327,579	245422	74.92
Niyriz White	163,809	127312	77.72
Total	908,196	753,976	83.02%
Unutilized Capacity	154,220		

- (xi) The producers and exporters are exporting material to other countries as is evident from the table below:-

White Cement	2000-01	2001-02	2002-03
Urmia White	0	15462	18822
Shomal White	4932	1884	492
Saveh White	55809	80513	64359
Neyriz White	37682	29293	11844
Total	98423	127152	95517

Clinker			
Urmia White	0	7148	9255
Shomal	0	0	0
Saveh White	70855	43064	102935
Neyriz White	53333	54020	39102
Total	124188	104232	151292
Clinker and Cement total			
Urmia White	0	22610	28077
Shomal	4932	1884	492
Saveh White	126664	123577	167294
Neyriz White	91015	83313	50946
Total	222611	231384	246809

- (xii) Domestic industry also referred to the US sunset policy bulletin, which states that no imports from a country after imposition of anti dumping itself suggests likelihood of recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in case of revocation of anti dumping duty and the exporters are required to establish that the product is unlikely to be dumped in the event of revocation of anti dumping duties. There is no such claim in the present case by Iranian producers.
- (xiii) Regarding export price from UAE to India, domestic industry submitted that the same is not reliable for determination of dumping margin because of the fact that the export price is not the actual price due to undertaking given by the exporter.

This is further corroborated by the fact that the exporter has exported white cement to neighboring country as also other countries at a price significantly below the undertaking price.

- xiv) In comments to disclosure statement, the domestic industry has reiterated that exports of cement clinker from the subject countries is significant in volumes and the price at which cement clinker has been exported should also be used as the basis for determination of likelihood of recurrence of dumping of white cement from the subject countries.

F.2 VIEWS OF THE EXPORTERS

- 25 None of exporter from subject countries filed any response with regard to the present investigation.

F.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 26 The Authority noted arguments made by the domestic industry on the methodology for determination of dumping and likelihood thereof. The Authority notes that this being a sunset review investigation, the Authority is required to examine continuation and likelihood of continuation or recurrence of dumping in the event of withdrawal of duty.

F.4 CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING

- 27 The Authority sent copies of the questionnaire to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c). No response has been received from any of the producer/exporters from UAE and Iran and importers in India on dumping and dumping margin. The Designated Authority, therefore, has no option but to proceed on the basis of best information available on records under Rule 6(8) of AD Rules for non-cooperative exporter which provides that:-

"In a case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the designated authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances".

NORMAL VALUE

- 28 Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:
- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
 - (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);
- 29 Designated Authority notes that none of the producer and exporters from subject countries has cooperated in the present investigation. Producer from RAK requested for extension of time also for filing of the response and Information. However, no Information has been filed by the exporter/producer. Under such circumstances, Designated Authority can not determine normal value in accordance to Section 9A (1) (c) (i), which

requires sufficient information with regard to price of the product in the domestic market in the ordinary course of trade. In view of the same, Authority examined possibility of determination of normal value based on other methodologies given in the Rules.

- 30 Authority further notes that because of non-cooperation from the exporter/producer, sufficient information with regard to exports to third country is not available in order to determine export price to appropriate third country in the ordinary course of trade. Examination of the information received with regard to exports to third countries from other sources shows that these exports are below the assessed cost of production and thus are at dumped prices. Under the circumstances, Authority can not determine normal value based on third country exports. The Authority has therefore no option but to determine normal value in subject countries as per cost of production including SGA and Profit.

UAE

- 31 Authority notes that none of the exporters or producers from UAE responded in the present investigations. A representative of Producer in UAE M/s. RAK attended the oral hearing. Authority advised the representative to provide Information relevant to the present investigations. No information has, however, been filed by the exporter.
- 32 Authority had written letter to Indian Embassy in UAE requesting them to provide Information about price of white cement in UAE. Indian Embassy informed that the whole sale price of product ranges from Dh\$ 21 – 25 per bag of 50 Kg. Considering exchange rates for the period of investigation, this comes to US \$ 114 – 136 per MT. Authority notes that the Embassy just informed the price prevailing in market in 2006 at the time of enquiry. No further information is available with regard to various terms & conditions of trade. Further, Authority is required to apply ordinary course of trade test before determining normal value as per price in the domestic market of the exporting country. As none of the exporter/producer cooperated, it is not possible to apply ordinary course of trade test and Authority therefore, has not proceeded on the basis of data/ information furnished by the Indian Embassy.
- 33 Under the circumstances, the Authority has proceeded on the basis of best information available/facts available with regard to normal value in the exporting country. The normal value has been determined on the basis of estimates of cost of production.

IRAN

- 34 Authority received Information of domestic price in Iran from the Indian Embassy in Iran. Authority notes that the same is based on a quotation obtained during 2006. Authority notes that mere price quotation is not sufficient for determination of normal value as the normal value means the

price of like article in the domestic market of exporting country in the "ordinary course of trade". In the absence of cooperation from any producer, Authority is not in a position to apply ordinary course of trade test. Therefore, the Information received from the Indian Embassy in this regard can not be used. Under the circumstances, the Authority has proceeded on the basis of best information available/facts available with regard to normal value in the exporting country. The normal value has been determined on the basis of estimates of cost of production

EXPORT PRICE:

35 Under section 9A (1) (b) export price means:

"export price", in relation to an article, means the price of the article exported from the exporting country or territory and in cases where there is not export price or where the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported articles are first resold to an independent buyer or if the article is not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as may be determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

36 The Authority sent questionnaires to all known exporters/producers for the purpose of determination of export price. None of the exporters/producers from subject countries filed any information.

37 The Authority notes that the sole exporter from UAE had given a price undertaking, under which the exporter could not have exported the material to India below the price which was earlier considered undumped price. Therefore, the price at which the exports were made in this period may not be representative of the price at which the exports might be made in the absence of price undertaking. Nevertheless, the Authority determined dumping margin in respect of exports made from UAE considering the price at which exports were made in order to determine dumping margin in respect such exports made at the undertaking price.

38 In case of Iran, the Authority notes that there are no known imports of the product concerned from Iran during the POI. Therefore, dumping margin in respect of POI exports can not be determined taking into account the actual data.

39 Upon initiation of investigations, the Authority advised Indian Missions in the exporting countries to collect relevant information. The information provided was examined, which showed as under.

a) In case of Iran, following information was provided

- (i) Exports of white cement from Iran to various countries for the years 2000-01, 2001-2002, and 2003-04 (as per Iranian financial year) in respect of white cement. Information has been provided for 2004-05 in respect of cement clinker, grey cement, aluminous cement and other hydraulic cement. Indian Producers have also provided information about exports of white cement for the years 2003-04, 2004-05, 2005-06 and 2006-07 upto July (as per Iranian financial year).

Information provided by the Indian Embassy and the domestic industry was examined further and it was found that substantial exports of the product under consideration are being made to a number of countries at a price which is below the normal value established.

- (ii) Based on the above, Authority notes that the producers from Iran are dumping subject goods in a number of countries and the dumping margins in respect of these exports is significant.
- (iii) Quotations were given by white cement producer in Iran to Indian Embassy which is not of POI. However, the Authority notes that since it is an offer for sales and because the prices indicated in this offer differ from the average prices for various countries as per summary customs data showed significant variations, the information could not be used in order to determine likelihood of recurrence of dumping.
- (iv) Cement basic price for export ratified by the Permanent Pricing Committee of Trade Promotion Organization of Iran showed some prices at which exports could be made. Even though this price is not for the POI, it is found that the export price mentioned in this document is lower than the estimates of normal value. Thus, the prices mentioned in this document also showed likelihood of recurrence of dumping from Iran in case of revocation of anti dumping duties.

b) In case of UAE, following information was provided

- (i) A producer in UAE provided information confirming the followings
- Capacity – 450,000 MT
 - Production during 2005 – 311686 MT
 - Domestic consumption in 2005 – 98030
 - Exports in 2005 – 204048 MT

According to the information on record, the company concerned is the sole producer of white cement in UAE. It was therefore concluded that the above information represented the relevant information for UAE. Further, even though the information is not strictly for the investigation period, the Authority has used the

information for the purpose of assessment of likelihood of continuation or recurrence of dumping from UAE.

- (ii) Authority received trade data regarding exports from UAE for 2004 to various countries, which states as under –

SN	Country	Volume MT
1	Belgium	216
2	Germany	231
3	Hong Kong	3,916
4	India	2,606
5	Indonesia	3,454
6	Iraq	490
7	Sri Lanka	334
8	Turkey	168
9	USA	1,058
10	Total	20,608

- 40 The Authority compared this information with (a) export volumes from UAE to World over, (b) the price at which UAE producer has exported to other countries and India on the basis of actual evidence available on record and concluded that the above information is not quite useful for the purpose of assessment of likelihood of continuation or recurrence of dumping from UAE, even though this Information received from Indian Embassy confirms that exports from UAE in other world markets are also at dumping prices. The Information provided covers just 10% of volumes exported from UAE.

- 41 Petitioner also provided evidence in terms of exports from the exporting countries as per information compiled by the respective Govt. authorities. Petitioner has also provided some bill of entries for home consumption showing imports of the product under consideration. Information provided by the petitioner showed as under –

Basis	Volume	Value	Price	Period
➤ DGCIS	0	0	0	POI
➤ Actual bill of entry	280	1282445	4580	Dec-04
➤ Exporting country data				
• 2004 calendar year	2606	7867941	3019	2004
• 2005 calendar year	4014	15898284	3961	2005

- 42 The Authority examined above Information also and found that these prices are also below normal value. Though, the bill of entry reflect the undertaking price at which exports have been made, yet, it is found that these exports were also at dumped price.

- 43 The Designated Authority advised Customs Port Authorities also to provide relevant information. Information received from one of the customs port showed imports of 280 MT white cement @ CIF Rs. 4580 pmt.
- 44 Considering the evidence provided by the Indian Missions, the foreign producers, customs port authorities and the Indian Producers, the Authority considers the following for determination with regard to dumping margin in the current investigation and likelihood of continuation or recurrence of dumping from UAE and Iran.
- a) Since there have been imports of the product from UAE, the dumping margin during the investigation period should have been determined on the basis of these imports. The Authority notes that even though the actual volume of imports claimed by the domestic industry is significantly higher than the imports evidence available on record, there is no material difference with regard to the export price. The Authority however, examined the export price considering the bill of entry on record, as certified by the customs port authorities, which shows positive dumping margin in case of UAE. Authority notes that the goods have been exported at the price at which the exporter had earlier given price undertaking. The Designated Authority had earlier determined that the said price was one at which the exports would not be at dumped prices. Therefore, the Authority considers that the price at which goods have been exported during the current investigation period may not be representative for the determination of dumping margin.
 - b) There are no imports reported in case of Iran and therefore dumping margin on the basis of actual exports can not be determined for Iran.
 - c) With regard to likelihood of recurrence of dumping, in case of UAE, the Authority relies upon the evidence available on record with regard to the price at which goods have been exported from UAE to Bangladesh and a number of other countries. In case of Iran, the Authority considered (i) the price at which goods have been exported from Iran to a number of other countries as per customs data, (ii) basic price for export ratified by the Permanent Pricing Committee of Trade Promotion Organization of Iran.
 - d) Considering the foregoing, the Authority has determined dumping margin as under-

	Normal value	Export price	Dumping margin	Dumping margin %
In case of UAE	US\$	US\$	US\$	
In the original investigation	93.54	61.54	32.00	52.00

(I) Considering actual shipments at undertaking price	118.10	88.00	30.10	34.20
(II) Considering exports to third countries				
a) Bangladesh (on the basis of bill of entry dated november 05)	118.10	48.00	70.10	146.04
b) Bangladesh (on the basis of bill of entry dated Feb 2004)	118.10	68.00	50.10	73.68
c) Indonesia (On the basis of Customs Data of Indonesia – weighted average price basis)	118.10	68.88	19.22	71.46
Considering exports to India				
d) Considering Indian Embassy data for exports to India for 2004	118.10	67.07	51.03	76.08
e) Considering data for exports to India for 2005 as made available by Domestic Industry	118.10	89.64	28.46	31.75
In case of Iran				
In the original investigation	86.43	40.20	46.23	115.00
(I) Considering weighted average exports to other countries in 2005 as made available by Domestic Industry	118.10	60.48	57.62	95.27
(II) Considering weighted average exports to other countries in 2003-04 as provided by Indian Embassy	118.10	55.04	63.06	114.57
(III) Considering price notified by Permanent Pricing Committee of Iran as provided by Indian Embassy	118.10	64.00	54.10	84.53

The Authority concludes that in case of UAE, the dumping margin determined on the basis of actual shipments is not useful for the reason that the export price represents the undertaking price. Dumping margin on the basis of exports to third countries ranged between 71-146%. In case of Iran, the dumping margins determined on the basis of exports to third countries ranged between 85-115%. While these determinations establish that dumping is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties, the Authority considers that it may not be appropriate to use these quantum of dumping margins for the purpose of determination of quantum of anti dumping duties. Since the dumping margin determined at the time of original investigation was based on actual shipments to India, the present investigations are in the nature of sunset review investigations and actual shipments have been made at undertaking price or there were no exports to India during relevant period, the Authority consider that it is appropriate

to consider the dumping margin determined at the time of original investigations i.e. U\$32.00(52.00%) in the case of UAE and U\$46.23 (115.00%) in the case of Iran for the purpose of fixation of quantum of anti dumping duties in the present investigation.

As regards likelihood of dumping considering the price at which cement clinker has been exported to India, the Authority notes that cement clinker has not been included within the scope of the product under consideration. Since the product itself is not included within the scope of the product under consideration, it is not appropriate to use import price of cement clinker to determine likelihood of recurrence of dumping.

F.5 LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING

45 In order to determine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, the Authority considered the following parameters: -

- a) Dumping margin determined in the original investigations.
- b) Dumping margin determined in the present investigations – wherever exports to India existed during the investigation period, the same were considered and dumping margin determined.
- c) The Authority determined the likelihood of dumping considering the price at which goods have been exported to other countries.
- d) Freely disposable present and potential capacities, considering known expansions undertaken by the foreign producers, prices prevailing in India, actual and potential volume of exports, export price from these countries to other countries.

46 On examination of these factors it is noted that

- (a) None of the producer/exporter has responded in the present investigations. It has not been demonstrated that withdrawal of anti dumping duty would not lead to likelihood of dumping and injury to the domestic industry and continued imposition of the duty was unnecessary to offset dumping. The Authority has proceeded on the basis of best information available/facts available.
- (b) Considering the price undertaking undertaken by the exporter, M/s. RAK from UAE, should the price undertaking expire, exports from UAE would be made at dumped prices. Therefore, the exports are likely to be at dumped prices from UAE if the anti dumping duty in force expires,
- (c) The producer in UAE has significant freely disposable capacities. Not only that the producer has significant unutilized capacities, but

also that the producer is having significant exports to various countries. The Authority considers that destination of these exports would depend on the price that a producer can fetch.

- (d) The statistics compiled in respect of exports through Dubai port showed exports of only 23625 MT, whereas M/s. RAK has itself admitting that the company is exporting 204048 MT. No information was provided by RAK with regard to the price at which 204048 MT has been exported. Nor any information appears to have been published in this regard. However, the information provided by RAK clearly showed existence of significant freely disposable capacities.
- e) The producer in UAE has exported the subject goods to other countries at significantly varying prices. Exports made to Bangladesh in a matter of less than two year differed by a significant amount of US \$ 20 pmt (which is quite significant, given the insignificant changes in the associated cost of production). The exporter thus appears to be willing to sell the material at prices that differ significantly.
- f) The prices at which goods have been exported to Bangladesh are at significantly dumped prices.
- g) The UAE producer has exported to India at prices close to undertaking prices. Therefore, it is evident that the prices of the exporter could reduce significantly once the present duties are revoked (cessation of present duties shall imply removal of price undertaking also).
- h) Dumping margins in respect of UAE exports to various countries are at significant variations, thus establishing likelihood of intensified dumping in case of revocation of anti dumping duties.
- i) The Iranian producers appear to be exporting the product at basic price for export fixed or ratified by the Permanent Pricing Committee. The prices so fixed are significantly lower than estimates of normal value. Should it be considered that exports to India would be made at these prices, it is evident that the dumping would recur in the event of revocation of anti dumping duties.
- j) The capacity, production, demand and consumption of white cement in Iran and UAE, as claimed by domestic industry and not disputed by other interested parties, are as under.

	Iran	UAE
Capacity	929835	450000
Production	759251	311686
Domestic demand	420000	98030

Exports	339251	204048
Unutilized capacity	170584	138314

- k) The Authority observes that there are significant unutilized capacities in both the countries. Additionally, both the countries are exporting to a number of countries and therefore possibilities of diverting third country exports to India are not ruled out.

In addition to exports of white cement, it is noted that there is export of clinker from these countries. Even though it would neither be appropriate to extend the scope of the product under consideration to include clinker nor would it be appropriate to consider imports of clinker as the imports of the product under consideration, it is evident that the exporters would prefer to export white cement as opposed to clinker. Thus, volume of exports and the price at which exports are being made are also relevant to determination of likelihood of dumping in the event of revocation of anti dumping duties. Considering the price at which clinker has been exported and value addition involved after clinker, the Authority notes that the exporters are likely to export white cement instead of clinker, at dumping prices, in the event of revocation of anti dumping duties.

- l) Export price from subject countries to a number of countries are significantly below not only the normal value but also the prevailing selling prices in India and non injurious price determined for the domestic industry;
- m) The Authority determined the likelihood of dumping considering the price at which goods have been exported to other countries. For the purpose, the Authority considered available information with regard to the price at which goods were being exported to other countries in view of non-cooperation by the subject exporters.
- n) It has not been demonstrated by the exporters that withdrawal of anti dumping duty would not lead to likelihood of dumping and injury to the domestic industry and continued imposition of the duty was unnecessary to offset dumping.
- o) Given significant surplus unutilized capacity with the producers/exporters in the subject countries and the significant differences in the price, the Authority holds that there is likelihood of exports from the subject countries to India in significant volumes at dumping prices. Having regard to the evidence concerning capacity, production, sales, demand, and prices, the Authority concludes that revocation of anti dumping duty would lead to renewed or intensified dumping and on this account, the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping. Having regard to the evidence on record and submissions made by the interested parties, the

Authority holds that revocation of anti dumping duty would lead to recurrence of dumping from the subject countries.

G. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

- 47 The Authority notes that this being a sunset review of antidumping duty already in force, continuation of material injury to the domestic industry, as well as likelihood of continuation or recurrence of material injury needs to be examined in the context of actual or likely imports of the subject goods from subject countries.

G.1 CONTINUATION OF INJURY

- 48 The Authority notes the arguments of the domestic industry that injury and causal link determination is not mandatory in a sunset review investigation. However, having established positive dumping margin for the subject goods exported from UAE during the investigation period and likely dumping from Iran and UAE, the Authority has also examined the injury, if any, suffered by the domestic industry during the same period. Authority has therefore examined whether the domestic industry has suffered injury during the period of anti dumping duties were in force.

G.2 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

- 49 The domestic industry has submitted that:

- (i) The Authority is not required to restrict to the requirements of Article 3 of the ADA and Annexure-II to the Rules in a sunset review case and causal link in review investigations is not required to be examined. WTO decision in the matter of OTCG has been referred to and relied upon.
- (ii) In sunset review investigation, in a situation where the performance of the domestic industry shows improvement, the Authority is required to examine likelihood of recurrence of injury in case the duties are withdrawn. Even if it is held that the domestic industry has not suffered continued material injury during the period of review, the positive state of the domestic industry would be disturbed once anti dumping duty is withdrawn. Further, mere positive state of the domestic industry is not a sufficient ground to allow the duty in force to expire without examining the likelihood of recurrence of injury. The same view has been held by the WTO Appellate Body in the matter of US – Sunset Review of Anti Dumping Duties on Oil Country Tubular Goods from Argentina.
- (iii) Injury to the domestic industry is likely to recur which is established by significant positive price undercutting, significant freely disposal capacities with Foreign Producers in the subject countries, price attractiveness of Indian market (higher prices in the Indian market vis-à-vis other third country market), dumping in third country markets by the producers in

subject countries. Analysis of the data/information in the present case suggests that injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties. In other words, both adverse volume injury and price injury to the domestic industry are likely in the event of revocation of anti dumping duties. Domestic Industry has quantified the potential volume injury and potential price injury that is likely in the event of expiry of the duty in force.

- (iv) In the instant case, there is no volume effect on performance of the domestic industry as there is duty in force and imports are limited. However, there is likelihood of increase in imports in case of revocation of duty given (1) excess capacity in subject countries, (2) huge Indian market, (3) price attractiveness of Indian market, (4) third country dumping.
- (v) Since there exists a price undertaking, the UAE producer was exporting the subject good to India at the price agreed in the undertaking earlier given. This does not mean that there is no likelihood of potential adverse price effect on state of the domestic industry. Since the current exports are made at undertaking prices, the current exports have naturally not had adverse price effect on the domestic industry. However, should the present duties be revoked, it is evident that the price undertaking would also be revoked. Should the present price undertaking be revoked along with present duty, it is evident that the exports from UAE would have significant adverse price effect on the domestic industry.
- (vi) Present capacity with the Foreign Producers is already in excess of demand in the exporting country. Already capacities are unutilized. Further, fresh capacities are being added. Capacity and demand of UAE producer is given below.

Particulars	Unit	Volume
Surplus freely disposal capacity	MT	330000
Future Expansion	MT	150000
Present excess capacity as % of demand	%	175%
Potential excess capacity as % of demand	%	400%

- (vii) The domestic industry in the coastal region is enjoying the sales as tabulated below which it would loose once the duty expires. This is because the Foreign Producers are having substantially higher excessive unutilized capacity. Thus, domestic industry assessed potential loss of sales, considering that the impact of dumping is restricted only to coastal region, even though it was argued that dumping was not restricted to coastal region.

Coastal Regions	Sales in POI
KERALA	*****
TAMILNADU	*****
MAHARASHTRA	*****

GUJRAT	*****
WEST BENGAL	*****
KARNATAKA	*****
ANDHRA PRADESH	*****
ORISSA	*****
PONDICHERRY	*****
Total Sales	299,624

- (viii) The influx of the exports of the subject countries with respect to the subject goods and that too at dumped prices would force or compel the domestic industry to reduce the selling price of the subject good in the Indian domestic market, as an alternative to loss of sales. The likely prices are shown in the table below. The comparison in the table below is done between net sales realization and landed price of imports.

		Unit	Price Effect	Volume Effect
			If price is reduced	If price is not reduced
1	Capacity in Subject country	MT	1,380,000	1,380,000
2	Demand in the Subject Countries		540,000	540,000
3	Surplus capacity in exporting country	MT	840,000	840,000
4	Production in Subject Countries	MT	1,140,000	1,140,000
5	Surplus utilised capacity in exporting country	MT	240,000	240,000
6	Surplus production	MT	600,000	600,000
7	Optimum Capacity Utilization	%	85	85
8	Surplus Likely production	MT	633,000	633,000
9	Demand in India	MT	550,000	550,000
10	Production of Domestic industry	MT	562,885	263,261
11	Sales of Domestic industry	MT	509,450	209,826
12	Sales of domestic industry in Coastal Region	MT	299,624	-
13	Capacity Utilization of Domestic industry	%	72.63	33.97
14	CIF Price if duty is revoked	US \$ MT	80	80
15	CIF Price if duty is revoked	Rs./MT	3,600	3,600
16	Landed Price including Basic Duty	Rs./MT	4,181	4,181
17	Present Selling price of domestic industry	Rs./MT	*****	*****
18	Likely Selling price of domestic industry	Rs./MT	*****	*****
19	Cost of Production of the domestic industry	Rs./MT	*****	*****
20	Profit Loss	Rs./MT	*****	*****
21	Likely profit/Loss	Rs./MT	*****	*****
22	Present Profit Loss on Domestic Sales	Rs. Lacs	*****	*****
23	Profit/Loss on total sales would be	Rs. Lacs	*****	*****
24	Present Cash Flow	Rs. Lacs	*****	*****
25	Likely Cash Flow	Rs. Lacs	*****	*****
26	Present ROI	%	15.66	15.66
27	Likely ROI	%	(15.64)	(15.64)

- (ix) Thus, the domestic industry would have to choose between declining sales volumes and reduction in prices. Should the domestic industry prefer to match the prices, the price declines would be too significant.

G.3 VIEWS OF THE EXPORTER / IMPORTER /OTHER INTERESTED PARTIES.

- 50 None of the other interested parties have advanced any arguments/submissions in this regard.

G.4. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 51 The Authority has taken note of various arguments raised by the domestic industry with regard to the material injury to the domestic industry.
- 52 The Authority has examined the submissions made by the domestic industry regarding the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry in case of revocation of duty. It is noted that duty was originally not imposed on M/s. RAK, UAE on the basis of a price undertaking offered by the exporter. The present investigation has been initiated in terms of Section 9A(5) of Customs Tariff Act which requires the Authority to determine whether the duty is required to be continued for a further period of five years and to examine the degree and extent of likely dumping and injury and the need for continuation or revocation of duty based on the information provided and arguments raised by various interested parties during the course of the investigation.
- 53 For the purpose of assessing current injury in the period of investigation, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports on the domestic industry. Positive dumping margin has been established in case of UAE and likelihood of recurrence of dumping at significant levels from each of the subject countries.

Assessment of demand and market share

- 54 For the purpose of determining the demand and market share the Authority considered sales of the domestic industry and imports from various sources. Demand of the product in India has been computed as the sum of domestic sales of the Indian Producers and known imports from various countries. Authority notes that the information provided by the DGCI&S has not reflected full volumes of import made. The demand so assessed is shown in the following table.

	Unit	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Sales of Domestic Industry	MT	503,120	535,815	526,507	539,860
Indexed	Trend	100.00	106.50	104.65	107.30
Imports DGCI&S - Excluding UAE and Iran	MT	2	70	0	0

Imports DGCI&S – Iran	MT	2	0	0	0
Imports Other evidence – UAE	MT	1,203	2,671	2958	3,662
Total Imports	MT	1207	2741	2958	3,662
Demand	MT	504327	538556	529465	543522
Indexed	Trend	100.00	106.79	104.98	107.77

- 55 It is seen that demand of the subject goods has shown a positive trend during the injury period. The sale of the domestic industry has improved during the injury period. Investigation has revealed that the exporters/producers in UAE and Iran are likely to resume export at dumped prices, should the present anti dumping duties be revoked at this stage.

Volume Effect

- 56 With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there is significant actual or potential increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the anti dumping rules provides as under:

"While examining the volume of dumped imports the said authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India"

- 57 Actual volume of imports during the period have been as under -

	Unit	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Imports volume					
UAE	MT	1,203	2,671	2958	3,662
Indexed	Trend	100.00	221.95	245.80	304.30
Iran	MT	2	0	0	0
Indexed	Trend	100.00			
Other Countries	MT	2	70	0	0
Indexed	Trend	100.00	3500		
Total imports	MT	1207	2741	2958	3,662
Indexed	Trend	100.00	227.01	244.99	303.30
Market share in imports					
UAE	%	99.67	97.45	100.00	100.00
Iran	%	0.17	-	-	-
Other Countries	%	0.17	2.55	0	0
Market share in Demand					
UAE	%	0.24	0.50	0.56	0.67
Iran	%	0	0	0	0
Other Countries	%	0	0.01	0	0
Imports in relation to Indian production					
UAE	%	0.22	0.49	0.52	0.63
Iran	%	0.00	-	-	-
Other Countries	%	0.00	0.01	-	-

- 58 The Authority notes that even though there is some increase in volume of imports as compared to base year, the volume of imports is quite low when considered in relation to production or consumption in India. The available evidence however suggests that volume of imports is likely to increase in the event of revocation of anti dumping duties.

Price Effect

- 59 With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows,

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

- 60 In a sunset review investigation, it is required to be examined whether there was a significant adverse price effect by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether there is likelihood of significant adverse price effect in case of revocation of anti dumping duty.
- 61 The net sales realization of the domestic industry is determined considering selling price, excluding taxes & duties, rebates, discounts and including transportation. Entire sales volumes of the domestic industry have been considered for this purpose. Landed price of imports has been determined considering weighted average CIF import price, with 1% landing charges and applicable basic customs duty. The comparison is done between net sales realization and landed price of imports for White Cement. A comparison for subject goods during the period under investigation was made between the weighted average landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market including transportation.

Rs. Per MT	UAE*	Iran
Net Sales realization of Domestic industry	*****	*****
Landed Value	5,150	-
Price Undercutting	*****	-
Price Undercutting (%)	13-15%	-

- 62 The Authority notes that since the current exports from RAK were made under price undertaking and exports there are no exports from other exporters, the price at which current exports have been made is not sufficient indicator of likely prices in the event of revocation of anti dumping duties. It is noted that the likely future prices can be significantly lower, given the price at which goods have been exported to other countries. It is

thus found that the imports are likely to cause significant price undercutting in the event of revocation of anti dumping duties and potential price undercutting would be in range from 9 % to 47%

- 63 The Authority further determined whether the domestic industry is likely to face price underselling in the event of revocation of anti dumping duties. For the purpose, the Authority considered actual and potential prices from UAE and potential prices from Iran and compared the same with non injurious price.

Rs. Per MT	Current	
	UAE	Iran
Non injurious price for Domestic industry	*****	*****
Landed Value	5,150	-
Price Underselling	*****	
Price Underselling (%)	30-32%	

- 64 The non-injurious price determined for the domestic industry was compared with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic producers by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI and providing reasonable profit on the capital employed. The analysis shows that the potential landed price of the subject goods from each of the subject countries are significantly less than the non-injurious price of the domestic industry. Designated Authority has also examined potential underselling margins. The potential underselling margins were 9 to 47% in the range of during the POI.

Economic parameters relating to the domestic industry

- 65 Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of the subject goods. Further Annexure II (iv) of the Rules lays down various factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual or potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

Capacity, Production, Sales and capacity utilisation

- 66 Status of the domestic industry with regard to capacity, production, capacity utilization and sales volumes over the injury period has been as under:-

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Capacity	730,000	730,000	775,000	805,000
Indexed	100.00	100.00	106.16	110.27
Production	537,257	549,239	563,814	584,104
Indexed	100.00	102.23	104.94	108.72
Capacity Utilization	73.60	75.24	72.75	72.56
Indexed	100.00	102.23	98.85	98.59
Domestic Sales	501,815	532,343	519,403	530,629
Indexed	100.00	106.08	103.50	105.74

- 67 It is noted that production and sales of the domestic industry showed a positive trend during the injury period. It is however noted that the dumped imports are likely to cause significant price undercutting and given significant freely disposable capacities with the subject foreign producers, it is likely that the domestic industry would either loose sales volumes or would be forced to reduce the prices in the event of revocation of anti dumping duties. Should the domestic industry prefer to maintain its prices, it is evident that the domestic industry would loose sales volumes and consequently its production and capacity utilization would suffer.

Productivity

- 68 Productivity of the domestic industry is given in the table below

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Productivity per employee(MT)	*****	*****	*****	*****
Productivity trend Indexed	100.00	101.14	102.99	105.24

- 69 The productivity of the domestic industry improved during the injury period. It is however noted that productivity would decline, should the present anti dumping duties be revoked.

Market share in Demand

- 70 Market share of domestic industry in demand is given in the table below.

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Market share in Demand				
Domestic industry	99.76	99.49	99.44	99.33
Subject Countries	0.24	0.50	0.56	0.67
Other Countries	0.00	0.01	0	0

- 71 It is noted that domestic industry has been able to maintain its market share with imposition of anti dumping duties. It is however noted that

market share of the domestic industry would decline, should the present anti dumping duties be revoked.

Profits, return on investment and cash flow

72. The present and likely status of profits, return on investment and cash flow of the domestic industry has been examined. Present status of these parameters of the domestic industry has been as under:

In Lacs	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Profit Before Tax	*****	*****	*****	*****
Indexed	100.00	66.30	50.86	77.90
Return on capital employed – GFA Basis	22.10	16.71	11.90	14.82
Indexed	100.00	75.60	53.83	67.06
Return on capital employed – NFA Basis	34.33	26.82	14.94	19.15
Indexed	100.00	78.12	43.53	55.77
Cash Profit	*****	*****	*****	*****
Indexed	100.00	73.20	62.52	87.99

73. It is noted that profits, return on capital employed and cash profits showed a deterioration over the injury period. Further, potential situation with regard to these parameters also shows a significant deterioration, given the level of price undercutting and price underselling the imports would cause in the event of revocation of anti dumping duties. Should the domestic industry be selling at prices matching with import prices, it is evident that the domestic industry would be faced with significant financial losses, negative return on investments and negative cash flow.

Employment and wages

74. Information regarding employment and wages is given in the following table. It would be seen that there is no adverse effect on employment and wages.

	Unit	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Employment	No	*****	*****	*****	*****
Indexed	Trend	100.00	101.08	101.89	103.31
Wages	Rs. Lacs	*****	*****	*****	*****
Indexed	Trend	100.00	114.01	116.71	119.66

Inventories:

75. Authority has examined the inventory level of the domestic industry, which is given in the following table:-

MT	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Inventory	16,785	17,006	16,082	18,943
Indexed	100.00	101.32	95.81	112.86
Inventory as % of domestic sales	3.34	3.17	3.05	3.51
Indexed	100.00	95.13	91.55	105.18

- 76 Inventory levels with the domestic industry though increased, the same is not very material.

Growth

77. On examination of various economic parameters of the domestic industry, it is noted that various volume and price parameters of the domestic industry showed positive trend, which is due to anti dumping duty in force against subject countries. However, given likely adverse volume and price effects that the imports would have in the event of revocation of anti dumping duties, it is evident that the growth of the domestic industry would be adversely affected with the revocation of anti dumping duties.

Magnitude of dumping

78. It is noted that the dumping margins are more than limits prescribed and are at significant levels. Dumping margins determined are as follows:

As determined in original investigation	
➤ UAE	52%
➤ Iran	115%
Determined in current investigations -	
UAE	
➤ Considering actual shipment at undertaking price	34.20%
➤ Considering exports to third countries – Bangladesh	146.04 %
➤ Considering exports to third countries – Bangladesh	73.68%
➤ Indonesia – on the basis of Customs Data of Indonesia – Average Price	71.46%
Considering Indian Embassy data for exports to India for 2004	76.08 %
Considering data for exports to India for 2005 as made available by Domestic Industry	31.75%
Iran	
➤ Considering weighted average exports to other countries in 2005 as made available by Domestic Industry	95.27%
➤ Considering weighted average exports to other countries in 2003-04 as provided by Indian Embassy	114.57. %
➤ Considering price notified by Permanent Pricing Committee of Iran as provided by Indian Embassy	84.53. %

It is evident that whenever exports have been made, these have been made at significant dumping prices.

Ability to raise capital and investment

79. It is noted that the ability to raise capital investment of the domestic industry has not been adversely affected given the anti dumping duty in force and the fact that both the companies are multi product companies. It is however noted that J. K. White is now substantially into the present product and any long term adverse impact can have significant adverse impact on the company.

640 GI/07-11

Factors affecting domestic prices

- 80 Change in cost structure if any, competition in the domestic industry have been examined for analyzing the factors other than dumped imports that might affecting the prices in the domestic market. It is noted that the landed value of imported material from subject countries is likely to be significantly below the selling price of the domestic industry and is thus likely to cause significant price undercutting in the Indian market. It is also noted that there is no viable substitute to this product and the domestic prices compete with one another along with the landed value of the imported goods. Given the nature of the product, substitution of domestic product with imported is inevitable, should the imported product be found significantly cheaper than domestic product.
- 81 Evidence provided by the domestic industry showed that there has been significant adverse reaction in terms of prices of the domestic industry, whenever imports have been reported in the market. Such being the case, the Authority notes that revocation of anti dumping duties is likely to have significant adverse impact on the prices of the domestic product in the market.

Magnitude of injury and injury margin

82. The non-injurious price including transportation cost determined by the Authority has been compared with the landed value of exports for determination of injury margin. The weighted average injury margins have been found to be significant.

OTHER KNOWN FACTORS AND CAUSAL LINK

83. It has been argued by the domestic industry that the conditions of Article 3.3 of ADA do not apply in the context of sunset review.
84. notwithstanding, the Authority has examined causal link between the likelihood of injury and dumped imports from the subject country. The Authority examined whether other listed known factors could have caused or are likely to cause injury to the domestic industry.

Volume and prices of imports from other sources

85. It is noted that there are practically no known imports of the product under consideration from other countries. Only UAE is exporting material to India, volume of which is also not very significant in terms of production/consumption in India and it is also noted that in case of Iran there is great likelihood of export of the subject goods to India in case of revocation of duty

	Unit	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Imports volume					
➤ UAE	MT	1,203	2,671	2958	3,662
➤ Iran	MT	2	70	-	-
➤ Other Countries	MT	2	0	0	0
Total imports	MT	1207	2741	2958	3,762

Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

86. It is noted that the demand of the product under consideration has not registered negative growth. Thus, contraction in demand is not a possible reason which could have contributed to injury to the domestic industry.

	Unit	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Demand	MT	504327	538556	529465	543522
Indexed	Trend	100.00	106.79	104.98	107.77

87. No evidence of change in consumption pattern has come to the notice of the Authority.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

88. The subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. The Indian Producers competes among one another and at the same time compete with the landed price of the subject goods. Nature of the product is such that the price in the price can be easily influenced by the landed price of subject goods. Should the imported product be cheaper, there would be increased dependence on the same.

Developments in technology and export performance

89. It is noted that the technology for production of the product has not undergone any material change nor there is any likely changes in future. Developments in technology, therefore, does not appear to be a possible factor of injury. It is noted that the domestic industry has exported small quantity of subject goods during the POI that does not substantially affect the operations of the company. The export performance of the domestic industry is thus insignificant if compared with the entire sales of the domestic industry. In any case, neither export performance of the domestic industry deteriorated nor the Authority has considered export volume and value in determining current injury to the domestic industry.

Productivity of the Domestic Industry

90. It is noted that productivity of the domestic industry has shown a growth. Possible decline in productivity does not appear to be a cause of injury to the domestic industry.
91. It is thus concluded that domestic industry has not suffered material injury. However likely injury to the domestic industry in the event of withdrawal of anti dumping duty would be due to dumped import.

Factors establishing causal link

While the above parameters establish that domestic industry has not suffered injury, the Authority notes that the following parameters establish that the injury to the domestic industry is likely to be by the dumped imports in the event of withdrawal of anti dumping duty.

- (a) Imports from subject countries would result in significant price undercutting in the event of expiry of anti dumping duty.
- (b) Existence of significant price undercutting in the event of expiry of anti dumping duty is likely to result in consumers increasingly switching over to the imported material, given that the product is highly price competitive.
- (c) Even though the volume of imports in the investigation period was not significant, it is significant enough in establishing its likely impact in the event of revocation of anti dumping duties. It is obvious that revocation of anti dumping duties is likely to force the domestic industry to reduce the prices significantly.
- (d) As a result of revocation of anti dumping duties and consequent increase in imports of the product under consideration, the domestic industry would be forced to either reduce its prices or loose sales volumes. Should the domestic industry be forced to reduce the prices, its profitability, cash flow and return on investment would be adversely and materially affected. Should the consumers increasingly switch over to the imports, domestic industry would lose sales volumes. Thus, in either situation would result in likely injury to the domestic industry.

It is thus evident that the domestic industry has recovered from the past effect of dumped imports. Such recovery would be prevented if the anti dumping duties in force are allowed to expire at this stage. Expiry of anti dumping duties would result in domestic industry once again facing injury from such dumped imports. Injury to the domestic industry would therefore be likely from such dumped imports.

LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

92. The domestic industry has argued that the requirement under sunset review is to examine whether revocation of anti dumping duty is likely to lead to continuance or recurrence of injury to the domestic industry and therefore, any examination based on the factors listed for a threat analysis would be flawed. Therefore, all such factors brought to the notice of the Authority, have been examined, to find if there is a likelihood of continuation of injury in the event of withdrawal of the duty. The Authority has determined that the subject goods are continuing to enter the Indian market at dumped prices or are likely to be exported at dumped prices from the subject countries in the event of withdrawal of anti dumping duties. It is pertinent to examine whether injury to the domestic industry is likely to recur due to these dumped imports if the duty is removed. It has already been established that the actual landed value of imports from the subject countries without the antidumping duty were below the non injurious price determined for the domestic industry.
93. In addition to the examination of continued injury, likelihood of continued or recurrence of injury to the domestic industry has also been examined by the Authority on the basis of information and evidence presented by various interested parties during the course of the investigations. The Authority examined the likelihood of continuation or recurrence considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules, which states as under:

"A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter alia, such factors and;

- (a) *a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.*
- (b) *Sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.*
- (c) *Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports and,*
- (d) *Inventories of the article being investigated.*

94. None of the exporters/producers from any of the subject countries as well as any of the Indian importers/consumers have responded in this review investigation except dealt earlier.. The domestic industry has provided information regarding capacity, production and demand of subject goods of the exporting countries based on best available information with them. It is noted that factors such as the volume of imports over the injury period, the level of import prices of subject goods from subject and non subject countries, surplus/freely disposable capacities available with the exporting countries suggest that revocation of anti dumping duty would likely result in significant increase in volume of dumped imports from subject countries. In a situation where the goods have been exported to India in spite of anti dumping duty in force, the volume of dumped imports is likely to increase further, in case the present anti dumping duties are withdrawn.

95. In order to assess the likely effect of the expiry of measures in force, it is noted that there are clear indications that the subject countries have the potential to raise their production and export volumes. On the basis of dumping examination, it is likely that in absence of measures, the producer from subject countries would adopt a policy of dumped prices, which will further cause injury to the domestic industry, which has recovered and improvement has been shown due to the anti-dumping duty in place against dumped imports from subject countries. The possibility for lowering down the prices from the exporting producers from these countries cannot be overlooked and denied in view of dumping and likely dumping. Such a price behavior of exporters from subject countries coupled with their ability to deliver significant quantities of subject goods, would in all likelihood have a general price depressing impact on the price sensitive commodity market. The evidence, thus, shows that should the measures be revoked, there is likelihood of recurrence of injury to the domestic industry.

96. The domestic industry has submitted various evidence regarding the likely volume of imports from subject countries in a situation of revocation of duty and the likely prices at which such imports would be made and likely impact on the domestic industry due to such imports.
97. The domestic industry contended that the exporters from subject countries continued to export the subject goods at dumped prices in the Indian market and producers in the subject countries are likely to resort to dumping of subject goods in the Indian market due to excess capacities in subject countries and surplus available with them. None of the interested parties participated in the present investigation and co-operated thereby to establish there is no likelihood of the continuation and recurrence of dumping and consequent injury in the event of revocation of the anti dumping in force. The domestic industry repeatedly stressed that the price difference between the domestic and imported material has been so huge that there is no reason to believe that these subject countries would not divert significant volumes of the subject goods to the Indian market in case the anti dumping duties are withdrawn, more so when freely disposable capacities exist with the foreign producers.
98. The arguments and submissions made by the domestic industry were examined having regard to the information/evidence made available by the domestic industry and on record of the Authority about the present and potential capacity, production, sales, imports, exports, domestic demand, the price levels in respect of domestic sales, exports to third countries and India, likely prices of imports from the subject countries. In order to determine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, the Authority considered the following parameters:-
- (i) Dumping margin determined in the original investigations;
 - (ii) Dumping margin determined in the present investigations.— for the purpose, wherever exports to India existed during the investigation period, the same were considered and dumping margin determined. Where there were no exports to India during the investigation period, the Authority determined dumping margin in respect of exports to third countries and likelihood of dumping considering the normal value established and the benchmark being recommended.
 - (iii) Surplus unutilized capacities, present and potential, considering known expansions undertaken by the foreign producers, prices prevailing in India, past actual and potential volume of exports.
 - (iv) Other facts disclosed with regard to likelihood of dumping in so far as the same are relevant for likelihood of injury also.
99. On examination of these factors it is noted that:
- (a) The dumping margins are significant in case of subject countries;
 - (b) Export price from subject countries are significantly below the prevailing selling prices in India and non injurious price determined for the domestic industry;

- (c) it has not been demonstrated by the exporters that withdrawal of anti dumping duty would not lead to likelihood of dumping and injury to the domestic industry and continued imposition of the duty was unnecessary to offset dumping;
- (d) Considering that current exports from UAE are at undertaking price, there is likelihood of substantial increase in imports should the price undertaking expire with the revocation of anti dumping duty;
- (e) The producer in UAE has exported the subject goods to other countries at significantly varying prices. Exports made to Bangladesh on in a matter of less than two year differed by a significant amount of US \$ 20 pmt (which is quite significant, given the insignificant changes in the associated cost of production). The exporter thus appears to be willing to sell the material at prices that differ significantly.
- (f) Dumping margins in respect of UAE exports to various countries are at significant variations, thus establishing likelihood of intensified dumping in case of revocation of anti dumping duties.
- (g) The Iranian producers appear to be exporting the product at basic price for export fixed or ratified by the Permanent Pricing Committee. The prices so fixed are significantly lower than estimates of normal value. Should it be considered that exports to India would be made at these prices, it is evident that the dumping would recur in the event of revocation of anti dumping duties.
- (h) The capacity, production, demand and consumption of white cement in Iran and UAE are as under.

	Iran	UAE
Capacity	929835	450000
Production	759251	311686
Domestic demand	420000	98030
Exports	339251	204048
Unutilized capacity	170584	138314

The Authority observes that there are significant unutilized capacities in both the countries. Additionally, both the countries are exporting to a number of countries and therefore possibilities of diverting third country exports to India are not ruled out.

- (i) The producer in UAE and Iran has significant freely disposable capacities. Not only that the producer has significant unutilized capacities, but also that the producer is having significant exports to various countries. The Authority considers that destination of these exports would depend on the price that a producer can fetch.
- (j) In addition to exports of white cement, it is noted that there is significant export of clinker from these countries. Even though it is neither appropriate to extend the scope of the product under consideration to include clinker nor would it be appropriate to

consider imports of clinker as the imports of the product under consideration, it is evident that the exporters would prefer to export white cement as opposed to clinker. Thus, volume of exports and the price at which exports are being made are also relevant to determination of likelihood of dumping in the event of revocation of anti dumping duties. The Authority notes in this regard that the volume of exports of clinker is substantial. Considering the price at which clinker has been exported and value addition involved after clinker, the Authority notes that the exporters are likely to export white cement instead of clinker, at dumping prices, in the event of revocation of anti dumping duties.

- (k) Export price from subject countries to a number of countries are significantly below not only the normal value but also the prevailing selling prices in India and non injurious price determined for the domestic industry;

The Authority observes that there are significant unutilised capacities in both the countries. Additionally, both the countries are exporting to a number of countries and therefore possibilities of diverting third country exports to India are not ruled out.

	UAE	Iran
Capacity	450000	930000
Production	311686	759251
Capacity Utilization	69.26	81.64
Unutilized Capacity	138314	170749
Imports	0	0
Total Availability	311686	759251
Demand	98030	420000
Excess availability	213656	339251
Exports	204048	246809
Net excess availability	9608	92442
Net Excess Capacity	211970	263191

100. As there is surplus capacity in the subject countries, it is noted that there is likelihood of exports from the subject countries being made in Indian market. Having regard to the evidence regarding capacity, production, sales and demand on record, it is noted that withdrawal of anti dumping duty would lead to intensified dumping and consequent injury and on this account, continued imposition of the duty is necessary to offset dumping.
101. It is noted that the exporters have not participated and co-operated with any convincing evidence on record that injury will not recur in event of withdrawal of measures. Having regard to the evidence regarding capacity, production, sales and demand on record, it is noted that withdrawal of anti dumping duty would likely to lead to continuance or recurrence of injury to the domestic industry.
- Having regard to the evidence on record and submissions made by the interested parties, the Authority holds that revocation of anti dumping duty would lead to recurrence of dumping from the subject countries.
102. In view of the above the Authority is holds that dumping and injury is likely to continue or recur if the duties are revoked.

H. Determination of non-injurious Price and Injury margin

103. In their post disclosure submission the domestic industry has raised a number of issues regarding computation of non-injurious price for the domestic industry and comparison of the same with the landed value for the purpose of injury margin determination. The issues raised have been examined by the Authority and the Non-injurious Price for the subject goods has been worked out taking into account the arguments raised and after a detailed analysis and scrutiny of information provided by the domestic industry in respect of its cost of production. Weighted average Non-injurious price for the domestic industry has been determined by the Authority as Rs****/-per MT.

I. FINAL FINDINGS:

104. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submission of interested parties or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of current and likely dumping and injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:
- i) The subject goods are entering the Indian market at dumped prices and dumping margin from subject country is significant and above de-minimis. The subject goods are likely to enter the Indian market at dumped prices, should the present measures be withdrawn.
 - ii) Even though the domestic industry has improved its performance over the injury period and not suffered injury, the injury to domestic industry would recur, should the present anti dumping duties be withdrawn.

J. RECOMMENDATIONS

105. Having concluded that the situation of the domestic industry has improved due to anti dumping duty in place, there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury on account of imports from subject countries, if the duties are revoked, the Authority is of the opinion that continuation of the measure is necessary against import from subject countries.
106. The Authority considers it necessary to continue with imposition of anti dumping duty on all imports of subject goods from subject countries in order to remove the injury to the domestic industry. The Authority recommends the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry.

107. Accordingly, the Authority recommends that definitive anti dumping duties as set out below be imposed by the Central Government on all imports of subject goods falling under customs heading 2523.21 of Schedule I under Chapter 25 of Customs Tariff Act originating in or exported from subject countries. The anti-dumping duty shall be the amount mentioned in column no.9 of the following table on all imports of subject goods falling under chapter 25 of the Customs Tariff, originating or exported from the subject territories mentioned below:-

Sl. No	Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount (US\$)	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2523.21	White Portland Cement	Any	UAE	Any country other than Iran	Any	Any	32	Per MT	USD
2	2523.21	White Portland Cement	Any	Any country other than Iran	UAE	Any	Any	32	Per MT	USD
3	2523.21	White Portland Cement	Any	Iran	Any country other than UAE	Any Producer	Any	38	Per MT	USD
4	2523.21	White Portland Cement	Any	Any country other than UAE	Iran	Any Producer	Any	38	Per MT	USD

108. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
109. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall normally be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party within the time stipulated for this purpose.
110. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (as amended).

CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority